के पीछे कल्पना है वह उसके साथ सहमत हैं, उसको ठीक और आवश्यक कल्पना समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि वह अपने विधि मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार का विधेयक निश्चित रूप से ला सकते है जिस विधेयक के पास होने पर राजनीतिक दलों को अपना सम्पूर्ण हिसाब-किताब प्रकाशित करने पर विवश किया जाय। वैसे तो भ्रष्टाचार आज बहुत बडे पैमाने पर सब जगह होता है और शायद करों से बचने के लिये अकाउन्ट्स कई प्रकार के रखते होंगे, उस में गड़बड़ करते होंगे, लेकिन आज यह जो दलील हैं कि हमने हिसाब किताब, लेखा जोखा रखने पर, उनको प्रकाशित करने पर मजबूर किया तो इसका कहां भरोसा है कि उसमें लोग गड़बड़ नहीं करेंगे? तो जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था कि यह इस बीमारी का सम्पूर्ण इलाज नहीं है, परन्तु इस दिशा में एक आवश्यक-और जरूरी पग है और जो मैं समझता हूँ कि आज लोकतन्त्र में लोगों की आस्था कायम रखने के लिए किसी न किसी रूप में उठाया जाना चाहिये। और मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने विभाग द्वारा इस कल्पना पर विचार करके इसको कार्यान्वित करने के लिए, और यदि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में संशोधन से काम नहीं लेना चाहते, तो कोई और विधेयक लाकर इस बीमारी का इलाज करें। इस भरोसे से मैं अपना विधेयक वापस लेता हूँ।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति है।

The Bill was, by leave, withdrawn.

16.17 hrs.

CENTRAL UNIVERSITIES (STUDENTS PARTICIPATION) BILL

श्री मधु लिमये (मुंगेर): **सभापति महोदय, आज जो प्रस्ताव मैं सदन के सामने रख रहा हूं वह इस बिल पर विचार कर उसे पास करने का प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इस पर लोकमत संग्रहित करने के हेतु से इसको परिचालित करने का यह प्रस्ताव है। और मंत्री महोदय से मेरी पहले ही बात इसके बारे में हुई है और उन्होंने कहा है कि इस प्रस्ताव के बारे में उनको कोई एतराज नहीं है। बल्कि वह चाहते हैं इसमें जो सिद्धान्त है उस पर व्यापक ढंग से समूचे देश में चर्चा चलनी चाहिये।**

सभापति महोदय, इधर कुछ वर्षों के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हमारे देश में आधुनिक शिक्षा का प्रारम्भ 112 साल पहले तीन विश्वविद्यालयों के प्रस्थापन से हुआ। उस समय बहुत कम लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे। जब आप और हम विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे तो तीन की संख्या बढ़ते बढ़ते 17 हो गई थी। लेकिन आज विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 70 हो गई है और 10 संस्थाओं को विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल है। हमारे जमाने में मुश्किल से सवा लाख छात्र विश्वविद्यालयों में पढ़ते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की जो ताजा रपट है उसके अनुसार पिछले वर्ष विश्वविद्यालयों में और कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 22 लाख से अधिक हो गई है। और एक ही साल के अन्दर करीब करीब इस संख्या में 14 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो बात बिल्कुल साफ है कि जब उच्च शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या 22 लाख हो जाती है तो छात्र आन्दोलन में एक ताकत और शक्ति जरूर आ जाती है। इस शक्ति को दबाने से, कुचल डालने से काम नहीं चलेगा। इस बात को हमें मानना चाहिये कि छात्रों में एक नई जागरूकता आयी है, चेतना आयी है। और अगर हम चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल रचनात्मक ढंग से किया जाय तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विधेयक के सिद्धान्त को किसी न किसी रूप में सरकार को कबूल करना पड़ेगा।

[श्री मधु लिमये]

अब इसमें दिक्कत यह है कि यह शिक्षा मन्त्रालय के तहत केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालय सीधे ढंग से आ जाते हैं। लेकिन जहां तक दूसरे विश्वविद्यालयों का सवाल है उनके ऊपर इनका कोई सीधा नियन्त्रण नहीं है। इसलिए मैंने चाहा कि यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन कानून में परिवर्तन करके विश्वविद्यालयों के अनुदानों का इस्तेमाल दूसरे विश्वविद्यालयों की और राज्य सरकारों की जो नीतियां हैं उनको प्रभावित करने के लिए किया जाय।

मेरे विधेयक में जो सुझाव दिये गये हैं संक्षेप में मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मैं यह चाहता हूं कि कानून के अनुसार छात्रों को अपने कालेजों में और विश्वविद्यालयों में अपना संघ बनाने का अधिकार हो और सभी छात्र इस संघ के सदस्य बने जब तक कि वह लिखकर नहीं देते हैं कि उन्हें सदस्य नहीं बनना है। प्रजातान्त्रिक ढंग से ये अपने संघ को चलावें।

दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि विश्वविद्यालयों की जितनी समितियां हैं, कोर्ट हो, ऐकेडेमिक काउन्सिल हो या एग्जीक्यूटिव कमेटी हो, अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग समितियां होती हैं। मैं चाहता हूं कि छात्र संघ को पूरा अधिकार दिया जाय कि वह इन समितियों में अपने प्रतिनिधि भेजे और ये प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को निभायें। विश्वविद्यालयों को चलाने का जो काम है अगर उसमें छात्रों को हिस्सा नहीं मिलेगा तो छात्रों में नई चेतना उत्पन्न हो पायेगी, न जिम्मेदारी की भावना आयेगी, न विश्वविद्यालयों के बारे में उनके मन में ममता उत्पन्न होगी।

आज दुनिया में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। शिक्षा मन्त्री स्वयं एक विद्वान आदमी हैं इसलिए वह तो जरूर जानते हैं कि पश्चिम के देशों में इन चीजों को लेकर क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। मैंने कुछ देशों के विश्वविद्यालय सम्बन्धी नये कानूनों को जानने की कोशिश की और पश्चिम जर्मनी जैसा देश, जो बहुत पुरानी परम्परा में विश्वास करने वाला देश है, मैंने देखा है कि पश्चिम जर्मन के कई विश्वविद्यालयों में छात्रों को इन समितियों में हिस्सेदारी मिलती है। जैसे बैडन बुरटैम्बर्ग सूबे में करीब करीब नौ विश्वविद्यालय हैं और इनमें समितियों की एक चौथाई सदस्यता छात्रों के प्रतिनिधियों की होती है। मारबर्ग विश्वविद्यालय में 20 प्रतिशत छात्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

जहां तक फ्रांस का सवाल है, फ्रांस की शिक्षा पद्धति बहुत ज्यादा केन्द्रीयकरण के ऊपर आधारित थी, पुरानी हो गई थी, नतीजा यह हुआ कि पिछले वर्ष ऐसा जबरदस्त आन्दोलन फ्रांस के छात्रों ने खड़ा किया कि दिगाल साहब की हुकूमत की जड़ों को भी उन्होंने हिला दिया। उसके बाद छात्रों की हिस्सेदारी का सिद्धान्त मान लिया गया और फ्रांस की असेम्बली में पिछले वर्ष इसके बारे में एक विधेयक पास हुआ है। वहां के शिक्षा मंत्री के भाषण का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह साहब कह रहे हैं:

"The major problem is the participation of students and this must be tried not only because the students have asked for it but because of transformation of relation between the students and teachers, of the introduction of team spirit and of the evolution which has meant that the teacher is always a students."

इंगलैंड में भी जहां आधुनिक विश्वविद्यालयों की परम्परा एक बहुत अर्से से चल रही है और जो यथास्थिति प्रिय देश है, वहां भी मिलीजुली कमेटी बनाई गई थी। विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, कालिजों के प्रिंसिपल्स और नेशनल यूनियन आफ़ स्टुडेंट्स के प्रतिनिधि इस मिली जुली समिति पर थे।

इस समिति ने अपनी जो रपट तैयार की है यह मूल रपट तो मुझे मिली नहीं लेकिन लंदन टाइम्स में इस का जो सारांश आया है उस से पता चलता है कि इन्होंने छात्रों की राय लेकर काम करना स्वीकार किया है ।

जहां तक छात्रों के कल्याणकारी कामों का सवाल है यह कमेटी मानती है कि उस में छात्रों को पूरा हिस्सा देना चाहिए। इसी तरीके से जिस को एक्सट्राकरीकुलम कार्य कहा जाता है उस के बारे में भी छात्रों की राय से काम लेना चाहिए । उस को ये लोग मानते हैं । लेकिन अनुशासन वगैरह का जहां सवाल है वहां इस कमेटी की राय है कि छात्रों के संघों का बड़ा दायित्व है और उस की राय लिये बिना अनुशासन प्रस्तावित नहीं हो पायेगा । परीक्षा, अभ्यास क्रम आदि के बारे में भी कमेटी चाहती है कि विचार विमर्ष हो ।

शिक्षा मंत्री जी का स्वयं मैंने एक लेख नाऊ नाम के साप्ताहिक पत्र में पढ़ा है । अब उस के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं वह अपना भाषण तो जरूर देंगे लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रों के बारे में अगर नया दृष्टिकोण हम नहीं अपनायेंगे तो भारत में भी उसी तरीके की आंधी उत्पन्न होगी जिस आंधी ने कि करीब करीब फ्रांस की हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया था ।

आज छात्रों के सामने कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ? सब से बड़ी समस्या शिक्षा के विस्तार के बारे में है । अब आजकल चारों ओर से हल्ला हो रहा है कि कालिजों के और विश्वविद्यालयों का आज जो विस्तार हो रहा है उस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाय । छात्रों को जो प्रवेश मिलता है कालिजों में और विश्वविद्यालयों में उस के ऊपर रोक लगाई जाय और उस को सीमित किया जाय ।

कई कारण बतलाये जाते हैं कि इतने रोजगार नहीं हैं, नौकरियां नहीं है और ये लोग जब स्नातकी वगैरह प्राप्त करके निकलते हैं तो उन्हें काम नहीं मिलता है और उन में गुस्सा उत्पन्न हो जाता है इसलिए छात्रों को पढ़ावो ही नहीं । बेकारी का इलाज आर्थिक प्रगति में तेजी लाना है, न कि कालिजों और विश्वविद्यालयों की जो संख्या है या उन में जिन छात्रों को प्रवेश मिलता है उस के ऊपर रोक लगाई जाय । छात्रों की संख्या सीमित करने की, नियंत्रित करने की साजिश चल रही है और यह सारा कार्य दकियानूसी नजरिया से हो रहा है । विश्वविद्यालय की शिक्षा का दर्जा घट रहा है, गिर रहा है इसलिए इस दर्जे को बनाये रखने के लिए या सुधारने के लिए छात्रों की संख्या सीमित करनी चाहिए यह एक दकियानूसी विचार हम लोगों के सामने आ रहा है । हिन्दुस्तान जैसे देश में अगर शिक्षा के विस्तार पर आप रोक लगायेंगे तो वर्तमान जो जाति व्यवस्था है, वर्ग व्यवस्था है उस को आप बदल नहीं पायेंगे । इस वर्ग व्यवस्था को जाति व्यवस्था को खत्म करने का शिक्षा एक सर्वोत्तम साधन है और इसलिए मैं चाहता हूं कि शिक्षा के विस्तार पर कोई रोक न लगाई जाय ।

जहां तक दर्जे का सवाल है मैं भी मानता हूं कि दर्जा गिर रहा है, लेकिन इस को आप सुधारना चाहते हैं तो आप को बुनियादी समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा । आज सब से बड़ा प्रश्न है माध्यम का । आज देहाती इलाकों में नये नये कालिज खुल रहे हैं । इन लड़कों से मेरी बातें होती हैं । अभी दो दिन पहले सभापति महोदय आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गयी थीं । वहां छात्रों से जरूर मिली होंगी और छात्रों ने आप को बतलाया होगा कि माध्यम को लेकर उन को कितनी तकलीफ़ होती है ? इसलिए जब तक आप माध्यम नहीं बदलेंगे और छात्रों को अपनी मातृभाषा से पढ़ने का और उस में इम्तिहान देने का मौका आप नहीं देंगे तब तक शिक्षा का

[श्री मधु लिमये]

स्तर आप कभी भी सुधार नहीं सकते हैं । आखिरकार शिक्षा के स्तर का क्या मतलब है ? आज जितनी बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थाएं हमारे देश में हैं, अब दुनिया में मान्यता मिलने का जहां तक सवाल है तो विज्ञान और गणित विषय को छोड़ कर और किसी विषय का छात्र मैं ऐसा नहीं देखता हूं जिसको कि बाहर मान्यता मिली हो । वह चाहे, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, भूगोल हो, समाजशास्त्र हो अथवा राजनीति हो, इन क्षेत्रों में हिन्दुस्तानी लोगों के नाम विदेशों में लिये जाते हैं ऐसा मैं तो नहीं मानता। इस का कारण यह है कि विषय ज्ञान से,आशय से ज्यादा जोर लफ्फाजी पर है। अंग्रेजी जो अच्छी लिखेगा उस को हम विद्वान समझते हैं हांलाकि वह विद्वान नहीं है । 20–30 या 50 साल पहले जो अंग्रेजों ने या अमरीकी लोगों ने लिखा है उस को वह दुहराता है । मगर यह पुराना ज्ञान जो भी अच्छे ढंग से अंग्रेजी में लिखता है उस को हम विद्वान मानते हैं । जब तक विद्वत्ता की यह गलत कसौटी को हम नहीं छोड़ते हैं और माध्यम के सवाल को तत्काल हल नहीं करते हैं तब तक शिक्षा का दर्जा नहीं सुधरने वाला है ।

तीसरी बात मैं यह कहूंगा कि आज छात्रों में जो असन्तोष है उस का सब से बड़ा कारण यह है कि परीक्षाओं के बारे में आज इतना घपला है, इतनी गड़बड़ है कि छात्रों के मन पर यह असर है कि सिफारिश और पैरवी के आधार पर ही परीक्षाओं में नतीजे निकलते हैं और आप इस बात को काट नहीं सकते हैं जब तक सिफारिश और पैरवी की दुनिया शिक्षा के क्षेत्र में चलती रहेगी और छात्रों के मन में जो असन्तोष है वह कभी भी दूर नहीं होगा ।

एक बात मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि एक ओर एजुकेशन कमिशन स्वयं मानता है कि अन्य देशों के मुकाबले में उच्च शिक्षा का जो विस्तार हमारे देश में हो रहा है वह बहुत कम है खास कर विज्ञान, कृषि और वैद्यक के क्षेत्रों में बिलकुल नाकाफी विस्तार हो रहा है । शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत बहुत बेकार जा रही है क्योंकि अधिकतर छात्रों को फेल किया जाता है । मैं दूसरे सूबों के विश्वविद्यालयों के बारे में नहीं जानता हूं लेकिन एक दफे महाराष्ट्र विधान सभा में सवाल किया गया कि इंटरमीजिएट की परीक्षा में जो छात्र फेल होते हैं और अक्सर 40 से लेकर 50 प्रतिशत: छात्रों का फेल किया जाता है तो इन फेल छात्रों में अनिवार्य विषय अंग्रेजी में कितने फेल है तब पता चला कि फेल छात्रों में 60 से 70 प्रतिशत : लड़के या लड़कियां अंग्रेजी में फेल होते हैं और कारण उस का साफ यह है कि अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय होता है । इसलिए इस के बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए ।

छात्रों के सामने बहुत सारी पाठ्य पुस्तकों की समस्या है, फीस की समस्या हैं, रहने की समस्या है । इन सारी समस्याओं का अगर आप हल निकालना चाहते हैं तो उन से सलाह मशविरा करके और उन के सहयोग से ही यह काम किया जा सकता है । शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन लाने के लिए छात्रों का सहयोग लेना जरूरी है । आज शिक्षा के क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि जिनका दिमाग बहुत पुराना है, जिनका दिमाग डा सहुआ है, ऐसे लोग वहां पर छाये हुए हैं । जो बड़े बड़े नौकरशाह है यहां नौकरी की मियाद खत्म होने के बाद या तो आप उन को राजदूत बना देते हैं या विश्वविद्यालयों के आप उपकुलपति बना देते हैं लेकिन नये विचार के जो लोग हैं उन को विश्वविद्यालयों में उच्च पदों में आज बिलकुल प्रवेश नहीं है । इसलिए विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में एक नई चेतना लाने के लिए छात्रों को

हिस्सेदारी देना आज निहायत जरूरी हो गया है ।

इम्तिहान और परीक्षा प्रणाली के बारे में सभी लोग जानते हैं और दूसरे देशों में भी उस के बारे में विचार किया जाता है । आज जो आप छात्रों की परीक्षा या इम्तिहान लेते हैं तो छात्रों को केवल एक पहलू की, उनकी गुणवत्ता के हिस्से की ही आप परीक्षा लेते हैं लेकिन उस छात्र का जो एक पूर्ण व्यक्ति भाव है उस के बारे में आप कोई जांच नहीं करते हैं । उस को परखने के लिए आप के पास कसौटी नहीं है । इसलिए उस के बारे में भी अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो आप को नये सिर से सोचना पड़ेगा ।

इस अपने विधेयक के बारे में सारा समय मैं ही लेने वाला नहीं हूं और मैं चाहता हूं कि अन्य माननीय सदस्य भी इस पर अपने अपने विचार प्रकट करें । मैं अपने भाषण को समाप्त करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि यह एक नये किस्म का विधेयक है । मैं नहीं चाहता हूं कि इस को जल्दी से पास कर दिया जाय । इस के बारे में अवश्य चर्चा होनी चाहिए । शिक्षा मंत्रालय को नये ढंग से सोचना चाहिए । जनमत जानने के लिए इसे प्रचारित करना चाहिए । विश्वविद्यालयों की राय इस के ऊपर लेनी चाहिए छात्रों की भी राय लेनी चाहिए ।

एक बात मैं शिक्षा मंत्री जी से जरूर कहूंगा कि कम से कम जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे बनारस है, अलीगढ़ है, दिल्ली है, वहां तो छात्र संघ कायम हो गये है, लेकिन पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में हजारों ऐसे कालेज हैं और दर्जनों विश्वविद्यालय हैं जहां पर छात्रों की कोई यूनियन नहीं है । मंत्री जी के लिये इस पर विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है और यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन के जरिये भी अन्य विश्वविद्यालयों में आप को इस को लाने की कोशिश करनी चाहिये ।

जांचों के बारे में बनारस विश्वविद्यालय का मामला आप के सामने है । जिस उप-कुलपति के खिलाफ आरोप हैं उसी को आप जज बनाते हैं तो आरोपों की जांच कैसे होगी । मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन इस बात का भी पूरा खयाल रक्खा जाना चाहिये कि जो आरोपी है, जिस के ऊपर इल्जाम है वह अगर जज बनता है तो कभी भी छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा । शिक्षा मंत्री को इस बात का खयाल रखना चाहिये । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> "That the Bill to constitute Students' Unions and to provide for their representation in Central Universities bodies, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st October, 1969."

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

> "That the Bill to constitute Students' Unions and to provide for their representation in Central Universities bodies, be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st October,1969."

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, एक बहुत ही अहम बिल हाउस के सामने आया है । इस के लिए हम श्री मधु लिमये को मुबारकबाद देते हैं । दरअस्ल तालिब इल्म हमारे देश की ताकत हैं, हमारे देश के चमन हैं और हमारे देश की नई उम्मीदें हैं । खुशी इस बात की है कि तालीम का विभाग भी हमारे एक ऐसे मंत्री के हाथ में है जो सही मानों में तालिब इल्मों की नब्ज पहचानता है, जो दिल में हरकत महसूस करता है और कुछ करना भी चाहता है ।

इस के साथ ही मैं प्राइम मिनिस्टर की भी

[श्री रणधीर सिंह]

तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने एक विभाग यूथ वेलफेअर का कायम किया है और सारे देश की तवज्जह और गवर्नमेंट की तवज्जह इस तरफ खींचने की तकलीफ गवारा की है ।

सब से बड़ी बात जो मैं इस बिल की मार्फत कहना चाहूंगा वह यह है कि देश में इस नौजवान तबके में एक आग सी लगी हुई है । यहां ही नहीं, सारी दुनिया का यह हाल है, लेकिन खास तौर से अपने देश में तालिब इल्म जो कुछ कर रहे है उस के लिये मैं उन की तारीफ भी करता हूं । अगर ऐसे हालात किसी दूसरे देश में होते तो तालिब इल्म पता नहीं क्या करते । वह जिम्मेदारी के साथ देशभक्ति का सबूत दे रहे हैं और देश को भूचाल और तूफान में नहीं डाल रहे हैं, इस से जाहिर होता है कि हमारे यहां के तालिब इल्म में जिम्मेदारी भी है और जो कुछ वह कर रहे हैं उस की जितनी भी तारीफ की जाय कम है ।

मैं जो बुनियादी चीज महसूस कर रहा हूं वह यह कि खराबी हमारे तालीम के सिस्टम में है । हमारी तालीम का जो सिस्टम आज है, मिनिस्टर साहब गौर फरमायेंगे, वह अंग्रेज के वक्त का, वोसीदा सड़ा हुआ और बरबादी शुदा सिस्टम है, जो गुलामाना तालीम देता है । सब लोग बाबू बनने की, नौकरी में जाने की, छोटी या बड़ी, ख्वाहिश रखते हैं, कोई अच्छे पेशे, जैसे दूकानदारी का पेशा है, खेती का पेशा है, सनत का पेशा है, की तरफ नहीं देखता है । हर एक 20-30 रु० का बाबू बनना चाहता है । हमारे यहां देहात में कहते हैं कि पटवारी बन जाय इस से बड़ा सिलसिला कोई नहीं । आज जो सिस्टम नौकरी की तरफ ढकेलता है, उस के बारे में हम को सोचना है । बजाय इस के कि यह सिस्टम नौकरी का हो, वाकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे जरात के जरिये या किसी और जरिये से लोग अपना काम करें, इस किस्म की होनी चाहिये । आज जो लड़के बेकारी के शिकार बनते हैं उन के लिये आप कहां से इतने कारखाने बनायेंगे ? सारा झगड़ा जो है वह इसी बात का है कि लड़के बी. ए. और एम. ए. पास करने के बाद क्या करेंगे इस देश में । जैसा बतलाया गया है आज करोड़ों आदमियों में बेरोजगारी है । आज हर एक बाप, गरीब किसान, हरिजन और मजदूर, जिस के भी लड़का है, यह समझता है कि मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, वह साहब बनेगा और हमारे यहां मनीआर्डर आयेंगे । लेकिन नौकरी मिलती नहीं है । घर में मां, बाप घुसने नहीं देते हम ने जेवर बेच कर, सब कुछ बेचकर तालीम दिला दी, और यह बेकार बैठा है, आप जानते हैं कि बेकार आदमी का दिमाग शैतान का घर होता है । तालीम हासिल करने के बाद सौ बातें उस के दिमाग में आती हैं । वह सोचता है कि यह क्या गवर्नमेंट है, इस को उल्टो । उस के दिमागमें मुल्क के खिलाफ सरगर्मियां होती हैं, और देश के लिये जो लोग तूफान बरपा करते हैं उन की सफ में वह जा कर खड़ा हो जाता है ।

मैं आज यह बातें क्यो कह रहा हूं? इसलिये कि जो हमारी आने वाली नस्ल है, जिन को देश को बनाना है, वह बड़े भारी इन्तशार का शिकार बनी हुई है । आप उन की नब्ज पहचानें इस में देश का भला है । वह चाहते क्या हैं ? पहली बात जो है वह यह कि वह महसूस करते हैं कि जो हमारे मौजूदा रूल्स एंड रेगुलेशन्स हैं, जो नियम लड़कों को समझाये जाते हैं वह इस तरह से मानो वह कीड़े मकोड़े हैं । प्रोफेसर और टीचर और लड़को के दर्म्यान आज बड़ा फर्क है । मुझे डा० राव माफ करेंगे, वह वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है स्कूल, कालेज और यूनिवर्सिटी लेवेल पर कि लड़कों और टीचर व प्रोफेसर के दर्म्यान आपस में बड़ा लम्बा चोड़ा फर्क है । उस को हमें दूर करना है । जब मैं मिशन कालेज में पढ़ता था,

उन दिनों हमारे प्रिंसिपल एक अंग्रेज हुआ करते थे, कितना एख्लाक था उन में, वह हम हिन्दुस्तानी बच्चों को साथ ले कर दस-दस, ग्यारह-ग्यारह मील अपनी गाड़ी में घुमाते थे, सैर कराते थे और उनकी बाते पूछा करते थे। इतना प्यार करते थे, हिन्दुस्तानी बच्चों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि आज जो हिन्दुस्तान के प्रोफेसर और टीचर हैं, उन का इस तरफ ध्यान नहीं हैं ? यह बात आज बच्चे महसूस कर रहे हैं ।

इस के अलावा जो हम देखते हैं वह यह कि आज कल जो सिस्टम एजुकेशन का है, जो इम्तहान आज कल होते हैं, उन में बड़ी खराबी है और मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें। लड़के यह समझने लगे हैं कि पास तो हो ही जाना है। मास कापीइंग चलती है। मास्टर से कह दिया कि अगर इतने परसेंट मार्क्स नहीं आये तो तुम्हारी तन्ख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हारी छुट्टी। मैं यह बात क्यों कहता हूं, इस वास्ते कि आज बुनियाद इस तरह की है, लड़कों में रेस्टलेसनेस है, इन्तशार है, और उन के दिमाग में इस तरह के इन्कलाब की बातें आती हैं। इस की तरफ भी मिनिस्टर साहब को ध्यान देना है। फारसी में एक कहावत है : **

अगर हमारे बच्चे में जो स्कूल या कालेज में है कोई गड़बड़ी हो गई और उन की बुनियाद गलत रह गई तो सारे देश का स्ट्रक्चर खराब हो जायेगा।

आम तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट कालेज हो वहां के स्टुडेंट्स की हालत बहुत खराब है। स्टुडेंट्स जो फंड देते हैं उस को वहां जो मैनेजमेंट है वही खा जाता है। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब इधर भी ध्यान दें और स्कूल लेवेल पर या कालेज लेवेल पर जो स्टुडेंट्स यूनियनें हैं उन को स्कूल या कालेज चलाने वाली जो बाडी है उस में बाकायदा रिप्रेजेन्टेशन मिले, उन में उन का पार्टिसिपेशन होना चाहिये।

इस के बाद मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारे स्टुडेंट्स में भी आनी चाहिये। छोटी छोटी सी बातों पर, मसलन रेल में चूंकि टिकट एग्जामिनर ने टिकट चेक कर लिया, उन को गलत काम नहीं करने चाहिये। यह नहीं होना चाहिए कि इतने पर वह चेन खींच ले, या कोई उन को इम्तहान में नकल न करने दे तो इस पर वह हड़ताल शुरू कर दें। यह बातें ठीक नहीं है। थोड़ी सी जिम्मेदारी उन के ऊपर भी है। मैं चाहूंगा कि इस बेरोजगारी के जमाने में, इन्तशार के जमाने में, जो लड़के हमारे देश की ताकत हैं, जिन के अन्दर एक बेकरारी है, वह इस तरफ ध्यान दें और इस में देर न कर के जल्दी करें।

जो बिल सर्कुलेट करने के लिये कहा जा रहा है, मैं पूरे जोर से उस की ताईद करता हूं और मिनिस्टर साहब से भी चाहूंगा कि वह सिर्फ जबानी ही वादा न करें, सही मानों में उस को इम्प्लिमेंट करें।

SHRI BALRAJ MADHOK (South Delhi) : The problem of student unrest and indiscipline is assuming great proportions, and every thinking man, whether he is a parent or just an individual, is feeling concerned about it. It will not serve to say that it is a world-wide phenomenon and so it must be here also. The problem prevailing in India is in many ways different from what is obtaining in France and other countries and it will be doing no good to a solution if we try to compare and equate the two and prescribe remedies on the lines of those adopted elsewhere.

The Bill before us tries to deal with one aspect of this problem and is welcome so far as it goes. But it will be wrong to think that simply by providing proper

** Question in Persian not furnished by the member.

[Shri Bal Raj Madhok]

opportunities of student participation we can solve the problem, though this is also one of the solutions.

Why is this unrest ? The first thing we have to keep in mind is that students are also part of the society. The general unrest, general indiscipline in society which is reflected everywhere including this House, influences the students as well and, therefore, to expect some different standards of behaviour from the students when we are following certain standards would be wrong and unreal. Hence unless the general climate of behaviour, of discipline in the country as a whole improves, whatever we may do, our schools and colleges will go on reflecting the indiscipline in society which exists today.

Then there is the question of educational problems. Till we became free, higher education was confined to a limited number of people. Now we have compulsory education; larger and larger numbers of pupils are going to high schools and from there to colleges. But the system of education continues to remain what it was before the advent of freedom. What was given to us by the British for the set purpose of producing clerks continues unchanged. Before freedom, this system had some national content in it; there was a general atmosphere of national fervour in the country and students used to take part in it. They were influenced by it; there was some kind of idealism abroad and in all kinds of agitation for freedom, students did take a creditable part.

Then some kind of moral influence was also there, the influence of teachers and political leaders. In most colleges, some kind of moral instruction was also imparted. After freedom, that idealism has gone. In the name of secularism, all moral education was finished in schools and colleges That national fervour has also disappeared. The result is that today our education has neither a moral content nor a national content. Without these, this education has become much worse than what the British wanted it to be. Students who are coming out are trained to be clerks. We do not have enough opportunities for them. The result is frustration, absence of values and no higher ideals.

When there is frustration all round, how should the boys behave ? Actually, as my hon. friend, Shri Randhir Singh, pointed out, the surprise is that our boys are not behaving much worse than they do today because conditions we see around are conducive to that type of behaviour. We have had three Plans. In each Plan, so much provision was made for so many engineering colleges ? But what has happened to the boys coming out ? Thousands of them are there without any avenues; they have spent Rs. 20,000 and Rs. 30,000 on their education, but now feel stranded. Therefore, the economic climate in the country and the moral environment in the country also have their influence on the minds of the students. Unless we can improve the economic climate, unless we can create moral values in the country, we cannot improve things much.

Before freedom, we used to condemn this educational system. But now we have found apostles and defenders of it. They say it produced Gandhi, it produced Tagore and it produced Nehru. Instead of making a serious effort to see what is wrong with the system, nothing is being done about it. Therefore, something has got to be done to improve the system itself.

In universities, students have leisure. Anyone who has been in college knows that there are lots of holidays and leisure there. Unless some constructive channel is found to utilise that leisure, it will be wasted in evil ways. Now colleges do not have playgrounds. Students have no other constructive activities. Result : they do not know what to do. Therefore, a few students who might have some political end or other ends could make use of them. All these aspects have to be looked into.

Coming to this Bill, this Bill deals with the student's participation in the affairs of the Universities and Colleges. As a teacher myself, I know that there are certain spheres in which I would not like the students to dabble. In purely academic matters as to

what kind of examination papers should be set and as to when the examination is to be held, I do not think students should have any say. But there are so many other things in a college in which students feel concerned, in which students have a direct interest and in which they should be consulted. We have before us the example of Nalanda University. In Nalanda we had the Acharya and we had the professors. In academic matters the Acharya was the complete master; but in respect of hostels and other amenities and such other matters there were students' councils and these students' councils used to take their own decisions. But here we find that in most of the colleges and universities the students are not given any say. The Principals and the teachers have become more and more bureaucratic. The moral influence which the teachers used to exercise over the students is disappearing. Even when the students come with genuine grievances, they are not looked into. I know in so many cases the students take the path of strike or agitation only when they have exhausted other means of getting these difficulties redressed. In many colleges, I think either there are no students' unions or if there are students' unions, the college authorities insist that a professor should be the chairman of the unions. Why not the students ? When we have a democratic system in the country, we want to deprive the students of their elementary rights. This is very wrong. Therefore, it is very essential that we should have well-defined students' unions in every college and university. Their functions should be well defined and the University authorities and the college authorities should give proper consideration to the view point of the students.

AN HON. MEMBER: What about RSS?

SHRI BAL RAJ MADHOK : The RSS can take care of itself. The students should be treated as equals in such matters. There is no question of a boss or servant or employee. The students and the teachers are the two wheels of the same chariot. They must work together and there should be some kind of co-operation. That will come when such unions are created, their powers and functions are well defined and the student representatives are consulted in all those matters which directly concern the students, their welfare, their sports, their canteens, their hostels, etc. There are many spheres where the students should get an opportunity to participate and discuss the affairs which concern not only the Universities but the whole country. The idea that the students should be kept cut of politics is wrong. Now we have given the right to vote to those who are 21 years and above and there are suggestions about giving the right to vote to those who are 18 and who are studying in the colleges. To keep them completely insulated or isolated from politics is completely wrong. Therefore, the student unions should undertake programmes through which political education can also be given to the students. So, in view of all these things, this Bill is welcome and it should be supported.

श्री जयपाल सिंह (खुन्टी): सभापति महोदया, लिमये जी ने कहा है कि ये पुराने पुराने जो लोग हैं, जो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़े हैं, जो विलायत में पढ़े हैं वे केवल अंग्रेजी में ही सोचते हैं। उनमें देशभक्ति की भावना नहीं है। वे पुराने रास्तों पर चलते हैं। उनकी इस बात की वजह से मैं आज उन्हीं की मातृभाषा में बोलना चाहता हूं। अगर मैं अपनी मातृभाषा में बोलूं तो वह एक शब्द भी उनका नहीं समझेंगे।

मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक रहा हूं। मैं प्राइमरी क्लासिस का शिक्षक रहा हूं। मैं दिन रात लड़के लड़कियों के साथ घूमता हूं। श्री मधोक दस मिनट तो इधर उधर की बातें करते रहे और आखिर में उन्होंने कह दिया कि वह इस बिल को सपोर्ट करते हैं। यह कहा गया है कि यह विधेयक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए लाया गया है। केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ही क्यों ? क्यों नहीं सारे देश के लिए ? श्री मधु लिमये ने

[श्री जयपाल सिंह]

कहा कि मन्त्री महोदय इस विधेयक के बारे में हां कह चुके हैं। मैं समझता हूं कि इस बारे में स्वयम् मन्त्री महोदय को कुछ कहना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि फ्रांस में यह होता है, पश्चिमी जर्मनी में वह होता है। हमें सोचना चाहिये कि हम भारत में हैं हम फ्रांस में नहीं हैं। यहां की जो संस्कृति है, हमें उसके अनुसार देखना चाहिये; यह नहीं कि आक्सफोर्ड में जो कुछ होता है, उसके अनुसार चलना चाहिये। श्री हिरेन मुकर्जी कलकत्ता से आक्सफोर्ड चले गए। वहां तो वह विलायती बन गए, लेकिन फिर उनको कलकत्ता लौटना पड़ा।

सवाल यह है कि विद्यार्थी विद्यार्थी हैं या शासनार्थी है। यह कहना कि अनुशासन एक दम खत्म हो गया है और यह है कि इस तरह की शिक्षा दी जा रही है, जिससे सारा अनुशासन गड़बड़ हो गया है, यह बिल्कुल गलत है।

श्री मधु लिमये की मधु वाणी है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि विद्यार्थियों से, लड़के-लड़कियों से कहां तक उनका सम्पर्क रहा है और कहां तक वह लड़के-लड़कियों से खेलकूद करते हैं।

श्री मधु लिमये : लड़कों से या लड़कियों से ?

श्री जयपाल सिंह : दोनों से। सवाल विद्यार्थियों का है। कौन पुरुष है और कौन स्त्री है, यह सवाल नहीं है। श्री मधु लिमये ने कहा कि लड़के यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। वह लोक सभा में क्या कर रहे हैं ? उन लोगों का यहां पर व्यवहार कैसा है ? लड़के लड़कियां रोज यहां आते हैं और उन लोगों के चालचलन को देखते हैं।

श्री मधु लिमये : और खुश हो जाते हैं।

श्री जयपाल सिंह : यह नक्लबाजी चल रही है कि इण्डोनेसिया में ऐसा हुआ, तो हम यहां भी वैसा ही करें; फ्रांस में ऐसा हुआ, तो हम यहां भी वैसा ही करें। बहुत से लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं, लेकिन उसके माने ये लोग समझे तक नहीं।

16.59 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

What is democracy ? It means that even the minority of one shall be heard. But here if you differ you will be beaten up We are talking of student participation. What on earth do you mean by 'participation'. Do you mean to say that the students should start lecturing, instead of the professors ? Is that what you mean ? I have been shocked to hear this....*(Interruptions)*. I have had the opportunity of seeing several universities and in fact I was asked to take up the vice-chancellorship of one of them.....*(An Hon. Member* : You deserve it) You deserve it more. But what is happening ? Students are satisfied if they get degrees without having to attend lectures or sit for examination. And that is being encouraged by my friends like Limaye and Madhok. I take just the opposite view. We must go for quality, not quantity. This is cheap popularity that we are trying to seek. I would not mention the name of the university, but they say there, "Well, make it 50 per cent". If you reduce it to 35 per cent, the students are satisfied. Then why not make it zero? What is this idea? We have got into the habit of blaming the English for everything. The British had a standard, I admit. Macaulay had a particular purpose to serve. Not only Macaulay, but I mean the British people as a whole. They had to build an empire and they had to produce clerks and certain other people. And that purpose was served. But much more than that was served.

17 hrs.

What is the use of these people telling us all this ? Sir, Tagore was a product of the British system; Gandhiji was a product of the British system; Jawaharlal Nehru was a product of the British system; Rajendra Prasad was a product of the British system. Let the hon. Members do a little bit of thinking. But they do not do that.

SHRI BAL RAJ MADHOK : You are twisting it. I said the defenders of that system are there.

SHRI JAIPAL SINGH : Who are they ?

SHRI BAL RAJ MADHOK : They are sitting there opposite. *(Interruption)*.

SHRI JAIPAL SINGH : It is not fair. The question is–regardless of the system–have we no character, no personality ? Are we not able to assert ourselves ? Nalanda was mentioned. There is the Gurukula system. What is wrong today, I find, is that we do not pay our teachers enough. They are not interested in teaching. They are interested in private tuition. They do not participate in the personal life of the students. That is where things have gone wrong.

I have been a member in Delhi of so many sports associations; not only in Delhi but everywhere. They are perfectly right in pointing out that they have no playground. What have the Members of Parliament done-- I want to know--to get to know the students ? Just to make speeches here ? These are very, very important points.

The point is why are they taking to some of the things-*pan dukan*, or cinema or something else ? Why ? Young minds have to be healthily occupied, not only inside the lecture-halls but outside also. And that has nothing to do with this Bill. When I read these aims and objects of the Bill, I was very surprised at Madhubani Madhu Limaye.

AN HON. MEMBER : A new title for Shri Madhu Limaye ?

SHRI JAIPAL SINGH : Because, Sir, only last week, the students in Ajmer were looking forward to listening to this Madhubani Madhu Limaye. He said he would come. It was broadcast. Not only the young students, boys and girls, but the entire city had gathered there.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA (Barh) : You will have to face the honey again.

SHRI JAIPAL SINGH : Are you going to give the honey ? *(Interruption)*. Sir, I regret I have to oppose this Bill because it is narrow-minded; it is unrealistic; it will do the students no good whatever. You cannot improve things by legislation.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : What happened in Ajmer ?

SHRI JAIPAL SINGH : Has he got any right to ask me that question ?

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI JAIPAL SINGH : The point is this.

There are certain things which cannot be improved by legislation. What is preventing students from having their own organisations ? Saying that the Principal must be the Chairman, this and that–I have never seen this type of nonsense, certainly not in the universities in Delhi or Ranchi or Calcutta. To impose something on the young students–boys and girls–is absolutely wrong. What is happening today is that the politicians--I am not blaming Mr. Madhubani but some people next door they have made students to become politicians. We saw what happened in Allahabad when Mrs. Eleanor Roosevelt went there. My memory is not so short. What happened to the students' unions ? They would not permit her to speak. Shrimati Vijayalakshmi Pandit had to plead with them. The rest of the story I will not complete, as I have not completed the Ajmer story. I will tell him the rest of it some other time.

Sir, I oppose this Bill for obvious

[Shri Jaipal Singh]

reasons. The sponsor of this Bill evidently has never been a teacher. He does not know how to handle young people. He thinks by legislating, he can make the students responsible.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Sir, the hon. member who preceded me has opposed the Bill. If the indication given by the Government now and then has got any truth, I think the Government is accepting in principle what Mr. Madhu Limaye has put in his Bill. Even last week when the matter was raised, I think the Home Minister said that the UGC, the Vice-Chancellors and the Education Ministry are seized of the problem and are trying to work out some solution of the burning issues involved.

I would like to go a little deeper into the question of indiscipline. The hon. Minister, writing in this journal, *Now*, a political and cultural weekly, dated 27th September, 1968, has said :

> "Discipline is good, but it must be evoked spontaneously, rather than be maintained by force".

Has this Government made any effort to see that there is that feeling of spontaneous discipline and behaviour on the part of students ? In the fifties, Government appointed a committee headed by Prof. Humayun Kabir— I think he was a member of the Cabinet then–which submitted a report, in which the whole question of student unrest and indiscipline has been linked with the position that the staff, professors and members of the faculties occupy today in our colleges and universities. Some members mentioned about the active part teachers are taking in day-to-day politics and student's affairs. Some complained that they are taking tuitions. Leaving that aside, with their present remuneration and the atmosphere in which they are asked to live, do you honestly hope they can rise above the level of an ordinary literate citizen in the urban centres ? You have not provided them with adequate houses within the university campus. You have not made any facilities for them to refresh their memories and to have constant access to the libraries. You have not even provided any facilities for them to live at a level which will make the students respect them.

There could be nothing more derogatory to the teaching community in this country than what has happened sometime back in Uttar Pradesh where a large number of teachers were arrested. I am not going into the merits, whether it is right or wrong--that is a different thing--but can you expect that such teachers would be in a position to command the respect of the students ? It would be impossible. Apart from the Kabir Committee there were many other committees. They have always linked this problem with the prestige of the teaching members. But, unfortunately, nothing has been done.

Even the University Grants Commission once decided that we should go in for more residential university and provide accommodation and living quarters for all the faculty members. So far nothing has materialised More and more universities are coming into being. Most of them are affiliated universities and not residential universities.

Therefore, the Government instead of going into the deeper causes of this unrest are just trying to look at the surface. They think that by imposing certain things they will be able to tackle the problem. It would be impossible.

Apart from that, there are a few other things. For example there is the Banaras Hindu University unrest. I reliably learn that when the elections to the union in the university took place, according to the rules and regulations of that union one student who was supported by the Vice-Chancellor of the university and who had his blessings was not qualified to contest in the elections. Still he contested but he lost the election. Afterwards he was creating problems probably with the connivance, directly or indirectly, of the Vice Chance-

llor of the university. Recently, I heard the news, that particular student who was supported by the Vice-Chancellor of the Banaras Hindu University was arrested during the mid-term elections and a pistol was taken from him for which a case has been registered against him. If such unwanted elements are to be supported by Vice-Chancellors of universities how can we expect the student community to have any respect for the head of the institution ? It would be impossible.

Why do these things happen ? It is because of political influence, communal feelings and other things. That is the curse of our social life today. What is the role of the Government ? The hon. Member who preceded me was very much irritated. He was angry that politicians are playing a very damaging role among the students by bringing in politics there. But I remember very well that after we found our party in Tamil Nadu the first thing our leader did was to make an appeal to the then Government in Tamil Nadu to arrive a gentlemanly agreement whereby no party, atleast as far as our State was concerned, would have any connection with any students union whether of a college, university or a secondary school. But the then Government was not prepared to come to an agreement. Unfortunately, what happened was that in the festivities that we have started after independence, after 1947, like Independence Day, Republic Day and the so many 'weeks' that we have gradually started, celebrating there has not been much of a popular enthusiasm. So, the government that were in power in the various States as well as the Centre tried to exploit the students to put up a big show. It gradually degenerated into the ruling political party trying to influence the students organisation. Then the other political parties also tried to win over the students and they also indulged in that kind of activity. Now all political parties are vying with one another to get the support of the student community. This is the unfortunate development. So, let us not take an attitude of who is winning the race. Without going into the previous history, let the government try to come to some kind of agreement with all political parties that no party should take any part in influencing the student life of this country. That would definitely be a step forward and I for one, on behalf of my party, can give word to the hon. Minister right now that we will scrupulously avoid taking part in the student life. If we do that, we can minimise or mitigate the student unrest that prevails in this country to a great extent.

Professor V. K. R. V. Rao has made certain very fine observations in his study. Probably he wrote this article during his tenure as Minister of Transport and Shipping. It is a very good thing that a man of his calibre, an educationist has come to this portfolio. I hope that during his tenure he would see to it that he would pursue the diagnosis he has made in those lines and try to find out some remedies so as to see that this problem is somewhat mitigated, if not altogether solved. At one place he says :

> "They do not trust us when we give them advice, which they dismiss as sermonising. They do not find consistency between our practice and our profession."

This is a very fine statement to make, but I do not know how far he will be able to persuade the professors and others in the university, the academicians and others who are connected with our educational institutions, to follow this precept.

So, the basic issue still is economic. We have to give a better life than what we are able to give today to the teaching community at large. For that I would stress only on two things, without going into the ramifications of the educational necessities. The earlier studies which were made about student indiscipline and the conclusions arrived at still hold good. Unfortunately, I have not brought the book of Kabir here about student unrest. I find it still holds good. They should go in for more residential universities. They should give a better status, even a face lift, to the teaching community. Unfortunately, I happened to have worked in a college for some three years.

SHRI JAIPAL SINGH : Why say "unfortunately?"

SHRI S. KANDAPPAN : Because, I had some bitter experience of the students clashing over my conduct. I left so much about it that I left the college by resigning the post, because I did not want to continue there any further. It so happened that I held ideas which were different from that held by some others. The students got themselves entangled in some of those philosophical ideas and took sides, some with the principal and some with me. The situation became so tense that curfew had to be imposed and an inquiry was ordered. The authority which was asked to conduct the inquiry happened to be the principal himself. Probably, the same thing is happening in Banaras. Only last week some of the students from Banaras represented to some of the Members of Parliament that the Vice-Chancellor was responsible for the trouble in the college. So, if you do not see to it that the person who is going to hold the inquiry is acceptable to them, it is not going to help your inquiry to solve your issues. Of course, I am not talking on the basis of any personal knowledge but on the basis of the representation that I received.

Instead of going into further committees, instead of appointing more and more committees and complicating matters, if they could only make a serious attempt to implement at least what they have already gathered by way of so many studies earlier, I am sure things will improve.

Here I will press for only two things. One is that you should try to make more allocation for residential universities and improve it. Another is that you should provide at least the basic minimum for a teacher to have a decent living. When a teacher stands in his class to lecture, even the tie that he daily wears is being observed and commented and if the tie is the same for seven days together, immediately pupils start whispering, "The poor fellow has got no other tie; so, he comes in the same old tie." Such kinds of talks are indulged in and they cannot help it. If a teacher is not able to meet even his little expenses over clean clothing and all that, how are we to improve the stature of teachers ? Unless we are going to give them that kind of a privileged position it would be impossible for them to command the respect of the students and unless they command the students, definitely you are not going to check indiscipline in this country. Even today in spite of the indiscipline due to so many causes--sociological, economical, political and others--in my part of the country even at the height of the language problem when the students were on the rampage I was able to see surprisingly that in some institutions the headmasters and the principles were so much respected that not a single student abstained from the class despite other students going to the compound and asking them to come out. Such is the commanding position of teachers and if we can really give it to the teacher, he can rise up to the occasion and hold and inculcate in the students a disciplined way of life. That is the only solution and the Government should seriously attend to it.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सभापति महोदय, इस समस्या के बारे में काफी कुछ सदस्यों ने कहा है। श्री मधु लिमये जी का बिल जो कुछ कहता है, उसके बारे में हमें परेशान नहीं होना चाहिये, चूंकि इस बिल में जो बातें कही गई हैं, उन बातों को कहीं कहीं पर लागू भी किया गया है। उत्तर प्रदेश में छात्र संघ का होना अनिवार्य है और हर एक छात्र को उसकी सदस्यता रखनी पड़ती है-यह उनके लिये आवश्यक है।

श्री मधु लिमये जी ने इस बात को कहा है कि इसको भारतीय रूप दिया जाय, सारे देश में ऐसी स्थिति पैदा की जाय, ऐसी अवस्था हो खासकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में यह आवश्यक समझा जाय कि वहां पर छात्र संघ होंगे उनके चुनाव होंगे, उनके जो कायदे-कानून होने चाहिये, वे होंगे। उन्होंने अपने बिल में जो ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्ज् दिये हैं, उनमें इस बात को समझाया है। आखिर उनकी यह मांग क्यों हैं ? श्री मधु लिमये के बिल का करीब-करीब सभी सदस्यों ने तहेदिल से समर्थन किया है, श्री जयपाल

सिंह ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका कुछ मात्रा में विरोध किया है, सभी मामलों में विरोध नहीं किया है। मेरा ऐसा ख्याल है कि श्री मधु लिमये जी का जो प्रस्ताव है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है, क्योंकि यह समस्या नौजवानों की है, यह समस्या तो आज की परिस्थितियों में उठेगी ही।

आखिर समस्या क्या है वह यही मांग करते हैं कि हमको अपनी जिम्मेदारी के मामलों में कुछ कहने का, कुछ सुनने का हक मिले। सभापति जी, संस्कृत में एक श्लोक है, आप तो स्वयं संस्कृत के पण्डित है, उस श्लोक का अर्थ यह है कि पांच वर्ष तक बच्चे का लालन-पालन होना चाहिये और बड़े प्यार से लालन-पालन होना चाहिये। पांच से दस वर्ष तक बच्चे पर अनुशासन लागू करना चाहिये और जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाये, उसको सहयोगी मानना चाहिये, साथी मानना चाहिये। समस्या यही है कि आज हम अपने बच्चों को सहयोगी मानने के लिये तैयार हैं या नहीं ? हमने उनको वोट तक का हक नहीं दिया है। मैं चाहती हूं कि छात्रों की तरफ से ऐसी मांग आने के पहले ही हमको अपनी तरफ से पियुपिल्ज रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में परिवर्तन लाकर 18 वर्ष की आयु के बच्चों को वोट देने का अधिकार देना चाहिये। आज प्रजातन्त्र में जिसको वोट देने का अधिकार है, वह अपनी बातों को सुना लेता है। आपने मध्यावधि चुनावों के पहले देखा—जब गन्ने के दाम की बात चल रही थी, खुद प्रधानमंत्री जी को उन लोगों को बुलाकर उनसे बातचीत करनी पड़ी। मध्यावधि चुनावों के पहले जब शिक्षकों की हड़ताल हुई और परिस्थिति गम्भीर होगई केन्द्र की सरकार और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिक्षकों से बात की।

प्रजातन्त्र में सम्मिलित मत की बड़ी कीमत हो जाती है। प्रजातन्त्र में एक और एक दो नहीं होते है बल्कि एक और एक ग्यारह होते हैं। आज जिनके पास सम्मिलित मत है, उनकी बड़ी कीमत है, उनकी बड़ी सुनवाई है। पिछले वर्ष जबकि यहां पर छात्र संघ का आन्दोलन हुआ था, कानून के कोर्स के सम्बन्ध में, तो मैं विश्वविद्यालय में गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में काफी नाराजगी थी। मैं जब गई और उनसे कहा कि आप जो बात कहते हैं वह हम लोगों से आकर नहीं कहते हैं बल्कि आन्दोलन शुरू कर देते हैं, आखिर हम लोग भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, अगर हमसे आप लोग कहें तो हम आपकी आवाज को जरूर उठायेंगे। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर साहब के दरवाजे पर हम महीने भर तक गये लेकिन हमें टाइम नहीं मिला और शायद मिनिस्टर साहब को इस बात की खबर भी नहीं होगी कि हम मिलने के लिए टाइम चाहते थे। उन्होंने कहा कि आज हमारी कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास वोट नहीं है। हम आपके चुनाव को विफल नहीं कर सकते हैं इसीलिये हमारी सुनवाई भी नहीं होती है। जब हम लोग सड़कों पर निकलते हैं तभी हमारी सुनवाई की जाती है। आप लोग पार्लियामेंट के सदस्य हमारे पास इसीलिए आये हैं क्योंकि आपको पता लग गया कि आपकी सरकार और आपकी पार्लियामेंट हिल रही है क्योंकि हमने हड़ताल की है, हम आन्दोलन मचा रहे हैं, हम दरवाजे और खिड़कियां तोड़ रहे हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जितना रुझान इस संसद् का और इस सरकार का उसके बाद हुआ उतना उसके पहले नहीं था। हम उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी नजर नहीं दौड़ाते हैं क्योंकि उनके पास मत नहीं होता है। आज बीस साल का लड़का बालिग नहीं है, यह एक अजीब विडम्बना है। 16, 18 और बीस साल के लड़के जो कि बी. ए. और एम. ए. पास कर लेते हैं उनको वोट का हक नहीं होता है। लेकिन एक बिल्कुल

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

निरक्षर आदमी अगर 21 साल का हो जाता है तो उसको जिम्मेदार समझ लिया जाता है। इसलिये मैं आपसे अपील करना चाहती हूं कि आप विधि मंत्री से कहें कि पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में परिवर्तन लाया जाए और 18 साल की उम्र से ही वोट का हक दिया जाये।

आज यह चीज दुनिया के और देशों में भी चल रही है। मैंने सुना है कि ब्रिटेन में भी यह मान्यता दी जा रही है और दूसरे देशों में भी इस बात को किया जा रहा है। हमारे देश में 18–20 साल की उम्र में वोट का हक मिलना चाहिए। मैं इसलिए इस बात को और कह रही हूं कि आप आंकड़ों को उठा कर देखें तो आपको मालूम होगा कि 35 साल से नीचे के जो नौजवान हैं उनकी जनसंख्या इस देश में 75 प्रतिशत है और 25 वर्ष से कम के जो लोग हैं उनकी संख्या 50 प्रतिशत है। तो जिस देश में 75 प्रतिशत उन लोगों की संख्या हो जो 35 वर्ष या उससे कम आयु के हों, उनको जिम्मेदारी के पद पर न लाना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और चाहती हूं कि उन्होंने अपने प्रांगण में, विश्वविद्यालय के दायरे में जो कुछ हक मांगे हैं वह आप बिना किसी जिद् के दीजिए। इस देश में महाभारत इसीलिए हुआ था क्योंकि दुर्योधन ने पाण्डवों को पांच गांव देने से भी इन्कार कर दिया था। मैं डा० साहब से अर्ज करना चाहती हूं कि आप बिना मांगे हुए ही उनको दे दीजिए, इससे आपको बड़ी सहूलियत होगी। वे भी महसूस करेंगे कि हमारी भी कुछ सुनवाई होती है। उनका अपना कोई नहीं है। मधुलिमये जी हैं और हम लोग हैं, यही सदस्य उनकी बातों को यहां पर उठाते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि उनकी अपनी जबान नहीं है, उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। किसान और मजदूरों का मत होता है, सरकारी कर्मचारियों का भी होता है लेकिन उनके पास कोई वोट नहीं है। इसलिए वे अपनी बात अगर कहलाना भी चाहें तो भी नहीं कहला सकते हैं, हम लोग अपनी मर्जी से जरूर उनकी बातों को यहां पर उठाते हैं। इसलिए यह हक उनको मिलना ही चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं एक विनम्र निवेदन और करना चाहती हूं कि यह जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, उस समस्या का समाधान क्या सिर्फ सरकार और सरकारी दफ्तर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको शिक्षा की पद्धति में आमूल परिवर्तन करना होगा और एक कदम उठाना होगा, वह कदम चाहे कितना ही मुश्किल क्यों न हो। इस बात को पर्दानशीनी में अब छुपाया नहीं जा सकता है। आपको एक कदम उठाना ही होगा। मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में गई और यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज में भी गई और वहां पर मैंने देखा कि वे जो यूनिवर्सिटीज हैं, अपने आप में एक संसार हैं। वहां पर मान लीजिए कोई पेट्रो-केमिकल उद्योग चलाना है तो उसका अन्वेषण कार्य करने के लिए यूनिवर्सिटीज को पैसा दिया जाता है। मान लीजिए बीस मिलियन डालर का कारखाना लगाना है तो उसका पांच परसेन्ट पैसा उस प्रोजेक्ट का सर्वे करने में लगता है। वह पैसा यूनिवर्सिटीज को मिलता है। उससे शिक्षकों को भी आमदनी होती है और जो विद्यार्थी उस पर काम करते हैं उनको भी आमदनी होती है। ऐसी व्यवस्था वहां पर चलती है।

हमारे यहां बी. ए., एम. ए. की डिग्री देने से क्या फायदा है? कागज के टुकड़े से बदतर उनकी हालत हो गई है। वह घूमते-फिरते हैं लेकिन कहीं कोई आसरा, सहारा

या सहूलियत उनको नहीं मिलती है। मेरा अपना एक भतीजा था वह एम. ए. पास करके डेढ़ महीने बैठा रहा, मैं देखती थी उस की हालत, देखकर तरस आता था, दिन में सोया हुआ है। मैं कहती थी कि यह सोने का कोई वक्त है ? वह कहता था कि मैं क्या करूं। मेरे सब साथी चले गए हैं मेरा मन नहीं लगता है। दो, तीन, चार साल तक हमारे नौजवान इसी तरह पड़े रहते हैं। उनकी क्या हालत होती है यह वही समझ सकते हैं। हम शायद महसूस भी नहीं कर सकते। इसलिए इस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए। जिस तरह से वहां की यूनिवर्सिटियों को आर्थिक विकास के काम में लाया गया है, अगर योजना आयोग इस बात की जानकारी रखता है कि देश की योजना की रूपरेखा कैसी बनेगी, तो मैं यह चाहती हूं कि यूनिवर्सिटीज को भी इस बात की जिम्मेदारी दी जाये और पांच, छः यूनिवर्सिटीज का एक कनसोटियम बना कर आर्थिक विकास की योजनायें बनाने के लिए उनको प्रश्रय दे, उनकी सहायता ली जाये। वह उस बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करें तो काफी हद तक यह समस्या हल हो सकती है। आप बेकारों के लिए योजना बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज में दिमाग की कमी है ? क्या यह सही नहीं है कि अगर वह अपने दिमाग को उसमें लगायें तो अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकती हैं ? मैं समझती हूं कि हमारे विश्वविद्यालय इस काम को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि वे सारी की सारी चीजें आपको यूनीवर्सिटी को देनी चाहियें जिस से विद्यार्थी उस में काम करें इस से उनको फ़ायदा होगा। और बी०ए०, और एम० ए० की डिग्री न दे तो भी काम चलेगा। इस तरह से आप शिक्षा के माध्यम में परिवर्तन करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि विद्यार्थियों के साथ हमारा जो सहयोग होना चाहिये वह नहीं है। हम क्या आदर्श उन के सामने पेश करते हैं ? मैं एक जगह विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिये पहुंची, वहां पर विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि जो राजनीति में रहने वाले नेता हैं, वे जिस तरह से आदर्श हमारे सामने उपस्थित कर रहे हैं, जिस तरह से मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं उस को देखते हुए आप कैसे हम में अनुशासन की बात करती हैं। पहले अपने रास्ते को ठीक कीजिये फिर हम से बात कीजिये। ये वे लोग हैं जिन के जीवन का इतिहास, जो इतिहास हमारे जीवन में लिखा जाता था, इन के जीवन में महीनों में लिखा जाता है, और जो इतिहास हमारा महीनों में लिखा जाता था वह इन के जीवन में रोज लिखा जाता है। मैंने जब बी०ए० पास किया था तो टेलीफोन करना नहीं आता था। तरीका नहीं जानती थी, लेकिन आज का पांच साल का लड़का दिल्ली से कलकत्ता टेलीफोन कर सकता है। जमाने को आगे बढ़ाया जाता है, वह पीछे नहीं आ सकता। पानी की धारा को बन्द कर दीजिये तो किनारे पर बहेगी और बाढ़ के रूप में छा जायेगी। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि प्रवाह को प्रवाह मिलना चाहिये, गति को गति मिलनी चाहिये। विद्यार्थी, उन की नौजवानी, उन का जोश और खरोश आगे बढ़ना मांगता है। उन को सहयोग आगे बढ़ कर के देना होगा, उनको सहयोग पीछे खींच कर नहीं दे सकते। अगर उस शक्ति को पीछे खींचना चाहेंगे तो वह बाढ़ बन कर के इधर उधर बह जायेगी।

मैं एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहती हूं। जो हम अभिभावक हैं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों, राजनीति के क्षेत्र में हों, विद्यार्थियों को हम को दूसरे नजरिये से देखना चाहिये क्यों कि वह अगर गलती करते हैं तो किस के पास जायेंगे अगर एक लड़का है 18,20 साल का क्या वह मां के पास नहीं आयेगा ? गलती

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

अगर करेगा तो जायेगा किस के पास। अगर मां बाप ध्यान नहीं देते तो मां बाप के पास अपने आंसू पुछवाने के लिये नहीं आता। दूसरी जगह भटकता है। इसलिये उन को अपनाने के लिये अपने कलेजे को बड़ा करना होगा क्यों कि वह गलती जन्म से नहीं करते हैं, परिस्थितिवश करते हैं। इसलिये हम को अपना अपना कलेजा बड़ा रखना चाहिये उन को अपनाने के लिये। इसीलिये मैं एक कविता पढ़ कर बैठना चाहती हूँ।

कहां मनुष्य है जिसे न भूल शूल सी बड़ी,
पर कहां मनुष्य है जिसे कमी खली प्यार की।
इसीलिये खड़ा रहा कि भूल को सुधार लो,
इसीलिये खड़ा रहा कि तुम मुझे पुकार लो।
पुकार कर दुलार लो, दुलार कर सुधार लो।

अगर दुलार कर के उन को सुधारने की कोशिश की जायेगी तो आज का सारे नौजवान, हमारे साथी, हमारे सहयोगी के रूप में हमारे साथ चलेंगे। इसलिये हमें अपने कलेजे को बड़ा करना हैं और अगर आप ने दुलार, प्यार से उस की भूल को सुधार कर उस को अपनाने की कोशिश की तो वह हमारा अपना ही रहेगा और हमेशा हमेशा के लिये अपना रहेगा।

DR. M. SANTOSHAM (Tiruchendur) : Sir, this Bill is very welcome at least for one reason, namely, it has brought to the attention of this House a very important problem of today, namely the students problem. I greatly appreciate the intention of the author, of the bill, but I find that the central theme of the Bill that he has placed before the House is that students must be given an opportunity to participate in the administration of the colleges and universities. And, with regard to this central theme of the Bill, I have my own reservations.

This Bill states that it is intended for the General universities. Because I do not have any knowledge about the Central universities, I take it that I should speak in a manner in which you would accept in the spirit of "what is sauce for the goose is sauce for the gander." From the knowledge of the universities that I know in the south, I would like to make a few remarks.

As a remedy for the student unrest it has been suggested that the Students Unions should be formed and the Unions should be allowed to have a share in the administrative process of the universities. I do not know if this is right. We love the students very much and we are interested in seeing that the student community enjoys the peace and tranquility that it deserves and that the student community should from day to day in such atmosphere progressively equip themselves with knowledge, yet, when they are in the universities. The extra love and affection that we try to show them, should not result in a harm to them. We should not try to please them by giving them responsibilities which they cannot carry out For instance, Sir, If student's representatives are going to take positions in university bodies it would be necessary that these students will have to face bitter elections. The period of time that they spend in universities is about six years. It is the maximum and during the major part of six years they are in the tender age of say, between 16 to 18. After that age of 18, some may have developed the necessary physical strength and mental stamina to go through an election, but even so, the student community would be compelled to face serious elections in the midst of studies and examinations periodically which will be harmful to them. And if they are compelled to indulge in harmful elections every now and then, year after year,in such an atmosphere I am absolutely certain,instead of solving the student unrest or student indiscipline,we certainly will be creating more and more student indiscipline. Student unrest does not limit itself to demonstrations in the streets or demonstrations in their Campus organised against teachers, masters and university administrators. But quite often one group of students fight another group of students. If, for the purpose of filling up places of responsibilities in universities, colleges and college unions

contest elections against one another then, one college will be fighting against another college,during electioneering. If Student unions are to elect their representatives to the university bodies you can very well understand the amount of unrest that will result. This will result in greater amount of indiscipline and would submit the students themselves into a hardship.

Therefore, Sir, this experiment of putting students to the travails of electioneering when they are seriously engaging themselves in studies and examinations is a very wrong thing to do. I feel that student indiscipline must be solved in a different way. It is possible that this overwhelming problem of student unrest has come up all over the world, not because of faults in student life itself, but due to adverse conditions obtaining after their student life period is over. The main reason why the students are in a mood of agitation and unrest all over the world, I feel, is because of the problem of the educated unemployed. Seeing the volume of the educated unemployed, these youngsters have a sense of frustration. They see their elders going about from place to place without having any means of livelihood. They find themselves dejected when they see such a scene.

Therefore, we must solve the unemployment problem. The educated unemployed should be fully utilised. Certain suggestions have been made already as to how they can be utilised in profitable occupations. Even during student life they can be given employment and given part-time jobs in universities and colleges in their offices, libraries and gardens so that they can earn for themselves while studying and thus get their spare time properly absorbed in an interesting work allotted. Outside the lecture hours and outside the laboratory hours they can occupy themselves profitably provided such facilities are given to them. It has been suggested that work such as survey work, statistics work and other studies of that nature can be handed over to universities and university students. It is a good suggestion. If the mind is engaged in that manner, student indiscipline can certainly to curbed a great deal.

Providing opportunities for the participation of students in matters of the University must also be considered, not in matters concerning their education, not in matters pertaining to universitiy academic life but certainly in matters connected wtih extra-curricular activities. University life has got so many other facts apart from studies; it has got sports activities, literary activities, fine art activities, magazines and so on. In all these, student participation would be most welcome and by this means, it will be possible for student-staff relationship to develop in such a manner as will pose no problem for the teachers in seeing to it that the students are disciplined in their classes.

The question of the adequacy of salaries to the professors and teachers has also been reffered to. It is true that the salaries paid not commensurate with the dignity that we should give to the teachers and professors. We expect from professors a great many things, but the salaries they are paid are not enough to enable them to keep themselves up to that status. In very many colleges, it is painful for one to see how the lecturers dress themselves, what clothes they wear and how the boys turn out to their classes. If you keep them side by side the teacher and the taught and take a photograph, the clothes that the students wear appear to be far superior to those of the professors. The boys come in a new dress every day and appear spectacular while the professors have to manage with one dress for a week or ten days. Such being the case, the tendency for students to nickname the teachers after the same coat or the tie he has been wearing for months without end. The situation in which the teacher is placed does not enable him to feel himself sufficient to the task. I do not even say that we should make the teacher actually feel superior to the students; but conditions are so deplorable that sometimes the teachers do not even feel themselves equal to the students.

Even when I was a student–that was years ago–I remember the first incident when I went to the city of Madras for my professional education. I was surprised to notice as a poor student the way other

[Dr. M. Santosham]

students had dressed themselves and were going to college. Then I found that apart from me, my teacher who was teaching physics was the only one coming to college on a rainy day with out even a raincoat to protect himself from the rain when the students were properly protected with raincoats. I am quite sure the teacher felt miserable. I felt really miserable for the teaeher. The situation is much worse these days. Disparity between living standard of the teacher and the taught is much more nowadays. Under such circumstances, students disrespect to teachers can only go on increasing. Therefore, I would suggest that the dignity of university teachers must again our attention.

Students must be provided sufficient distractions. One of the main reasons for student indiscipline is the absence of such constructive distractions. In large cities, they do not have enough space to go and have games they do not have adequate recreation for their intellectual talents and physical display during their leisure hours. It is one of the main responsibilities of those who are considering student problems to see that sufficient districtions are provided for them, distractions which are not harmful. A distraction such as election will certainly do harm to the student community and create hardship and come in the way of his education, but distractions of a different nature which will give students relaxation would be one of the good ways by which the student unrest problem can be solved.

Therefore, I am totally opposed to the proposal that student unions should indulge in elections and afterwards send their representatives to the universities where they will be full partners along with others in the matter of administration of universities. This is an incorrect approach. I would certainly say that in the matter of extra-curricular activities full participation of the students must be taken, but in the matters of academic nature, they should not have anything to do with the administrative machinery of the university on equal terms with elder educationists.

MR. CHAIRMAN : I have many hon. Members who want to speak.

श्री मधु लिमये : कुछ समय बढ़ा दिया जाए । बहुत से लोग बोलना चाहते हैं ।

SHRI CHANDRA JEET YADAV : You should extend the time. This is a very important topic.

MR. CHAIRMAN : I am trying to call everybody. There is a little priority.

श्री शशि भूषण (खारगोन) : सभापति महोदय, लिमये जी ने जो विधेयक रखा है इसकी आत्मा के साथ मैं पूर्णतया सहमत हूं । यह बहुत सामयिक विधेयक है ।

आज हमारे देश में तीन करोड़ बेरोजगार नौजवान हैं । हर साल पचास लाख की तादाद में बेरोजगार नौजवान बढ़ रहे हैं । विद्यार्थियों के सामने कोई भविष्य नहीं है । इस कारण से उन में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है । जब तक उनको एक नई दिशा नहीं मिलती तब तक विद्यार्थी जो विचलित हैं और बेचैन हैं, उनकी बेचैनी समाप्त नहीं हो सकती है ।

विद्यार्थियों को मीठी-मीठी बातें कह कर बहलाया नहीं जा सकता है । उनके सामने कुछ बड़े आदर्श भी रखने होंगे । मौनोपोली और सोशल वैलफेयर साथ-साथ नहीं चल सकते । क्या देश के विद्यार्थियों के सामने आदर्श सड़े-सड़ाये और गले हुए कुरप्ट लोग और मौनोपोलिस्ट होंगे ? विद्यार्थियों का आदर्श क्या हो इसके बारे में भी आपको निर्णय लेना होगा ।

विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में और उनके मैनेजमेंट में हिस्सा मिलना चाहिये, इसमें कोई शक नहीं और वे लेंगे । इस वास्ते आप आसानी से इसको मान लें । अगर आप नहीं मानेंगे तो विद्यार्थी शक्ति से भी ले सकते हैं । बहुत सी चीजें वे शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं ।

वे उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब वे 18 साल की उम्र में गोली खा सकते हैं, सेना के बड़े अधिकारी बन सकते हैं, इतिहास साक्षी है कि 18 साल की उम्र के नवयुवकों ने बड़े-बड़े काम किये हैं तो क्या वे किसी कालेज या विश्व-विद्यालय के मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उनको हिस्सा देना चाहिये ताकि वे मैनेज-मेंट में हिस्सा लेना सीखें। अगर हम उन्हें इसका अवसर नहीं देंगे तो वे दूसरी ओर जाएंगे।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि 18 साल के नवयुवकों को वोट देने का अधि-कार होना चाहिये। यह बहुत सही है। यह इसलिये होना चाहिये कि विदेशों में भी ऐसा है कि इंग्लैंड में और दूसरी जगह विद्यार्थी उन अधिकारों के लिये पहले पहल लड़े और आज इंग्लैंड में और दूसरे देशों में कुछ अधि-कार उन्होंने लिये और बहुत जल्द हम देखेंगे कि सारे यूरोप में 18 साल के नवयुवकों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। यह प्रवृत्ति जर्मनी में भी है, फ्रांस में भी है और भारत में भी है। अच्छा हो कि उनको यह मौका अभी दे दिया जाय। वर्ना क्या होगा? विद्यार्थियों को आज यह कहा जाता है कि वे राजनीति में हिस्सा न लें। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर राजनीति है क्या? जो हमारी समाज में विष-मता है, एक ओर पचास का तनख्वाहों में अन्तर है, सौ और पांच हजार का अन्तर है, जमीनों में अन्तर है, करोड़ और अरब पति एक तरफ हैं और गरीब दूसरी तरफ हैं, इस विषमता को विद्यार्थी नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? इसको समझना और इस विषमता को दूर करना ही तो राजनीति है। इसको दूर करना विद्यार्थियों का परम कर्त्तव्य है।

आप जानते ही हैं कि हमने अपने देश में बहुत अच्छे-अच्छे विधेयक पास किये हैं। लोगों के लिए हम उनको लाये हैं। लेकिन उन पर अमल नहीं हो सका है। यह खेद की बात है कि हमने अपने शिक्षकों को भुला दिया है। तीस लाख शिक्षक इस देश के गांव-गांव में मौजूद हैं। हम उन शिक्षकों को अच्छा वेतन, अच्छा कपड़ा और मकान नहीं दे सके। अगर हमने उन्हें आदर दिया होता और राष्ट्र के महान् कार्य में उन से सहयोग लिया होता, तो देश की स्थिति दूसरी ही होती।

अव्वल तो हमारे देश के बड़े मन्त्री और बड़े अधिकारी गांवों में जाते ही कम हैं, लेकिन जब कभी वे जिले की किसी बड़ी जगह में जाते हैं, तो केवल बड़े अफसरों को ही मिलते हैं; वे कभी विद्यार्थियों या शिक्षकों के प्रतिनिधियों से नहीं मिलते हैं। अगर हम गांव के स्तर से लेकर बड़ी से बड़ी परिषद् तक में शिक्षकों को सलाहकार के तौर पर रखें और उनके संगठनों को मान्यता दें, तो देश में परिवर्तन होगा। रूस, चाइना और आस-पास के जिन देशों में शिक्षकों को पूरा आदर और मान्यता दी गई, वहां उन्होंने उस देश की आर्थिक दशा बदल दी।

विद्यार्थियों को ये अधिकार देने पर किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन्हें निर्माण-कार्य और मैनेजमेंट के सम्बन्ध में सीखने का मौका मिलेगा। आज तो वे लोग गली-सड़ी दलदल में फंसे हुए हैं, बिरादरीवाद और जातिवाद की दलदल में फंसे हुए हैं और साम्प्रदायिक संस्थाओं में परेड करते घूमते हैं। उन्हें विकास का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। पंद्रह करोड़ विद्यार्थी और तीस लाख शिक्षक एक महान शक्ति हैं। इसलिए हमें उनकी संस्थाओं को बलवान बनाना चाहिए और उनसे सलाह-मश्वरा लेना चाहिये। हम ने इस देश में जो भी सामाजिक परिवर्तन करने हों, उन सब में उनका साथ लेना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सोशल वेलफेयर का सारा काम मन्त्री महोदय के अधीन आना चाहिए, जो कि वह शिक्षकों और विद्या-

[श्री शशि भूषण]

थियों के द्वारा करायें। कुछ थोड़े से अन्धे-लूलों या अनाथालयों और विधवाश्रमों को मदद करने से ही इस देश में सोशल वेलफेयर नहीं हो सकता है। हमें जाति के सम्बन्धों में परिवर्तन लाना होगा और इसके लिए लोगों को इनसेन्टिव देना होगा इस सम्बन्ध में हमारे डी० एम० के० के साथियों ने तामिलनाडु में एक नई दिशा दी है। अगर कोई हरिजनों के साथ सामाजिक व्यवहार करता है, शादी-विवाह करता है, तो वहां उसको मान्यता दी जाती है, नौकरी दी जाती है। अन्तर्जातीय विवाह और अन्तर्प्रान्तीय विवाह भी सोशल वेलफेयर का एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए।

लेकिन आज हम बिरादरीवाद से बहुत डरते हैं। चूंकि वोट लेना है, इसलिये हम सीधी-सीधी बात नहीं कर सकते। हम कबीर से भी पीछे चले गये हैं। वह चौराहे पर खड़े होकर पाखंडियों के खिलाफ बोलता था, लेकिन हम बिरादरीवाद के पाखंड के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। प्रजातन्त्र में बिरादरीवाद को मान्यता और आदर दिया गया है और उससे हमारा सारा डेमोक्रेटिक ढांचा बर्बाद हो रहा है।

अगर हमने देश में साम्प्रदायिक एकता और राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखना है, तो विद्यार्थियों और शिक्षकों को पूरा आदर और पूरे अधिकार दिये जायें। वे इस समाज को बदल सकते हैं। वे जात-बिरादरी के ढांचे को जला सकते हैं। बसें जलाने की उन्हें जरूरत नहीं होगी। बहुत सी पुरानी रूढ़ियों को उन्हें जलाना है। आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें एक दिशा दी जाये और यह विधेयक उस तरफ एक कदम है।

मैं यह विधेयक लाने के लिए श्री मधु लिमये को मुबारकबाद देता हूं। मन्त्री महोदय विद्यार्थियों के साथ रहे हैं। विद्यार्थियों को उनसे आशा है। वह शिक्षकों को आदर और मान्यता दें, उनके संगठनों को मान्यता दें और उनसे सलाह-मश्वरा करें।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : सभापति महोदय, मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूँ। भारत की कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं है। दिशा-शून्य शिक्षा बढ़ती जा रही है। अंग्रेजों द्वारा काल-प्रवाह पर छोड़े हुए चरण-चिन्हों पर भारत की शिक्षा नीति चलाई जा रही है। इसी लिए आज की यह परिस्थिति पैदा हुई है। स्वतन्त्रता को 21 साल से ऊपर हो गये। परन्तु शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हेतु कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया। गांधी जी ने इस दिशा में बुनियादी शिक्षा पद्धति अपना कर अपने तरीके से प्रयास आरम्भ किया था और उस पर व्यावहारिक कदम उठाये थे, लेकिन दुख इस बात का है कि स्वतन्त्रता के बाद उन्हीं के चरण-चिन्हों पर चलने का दावा करने वाली सरकार ने उस प्रयास को भी तिलांजलि दे दी। छात्र जगत में आज कोई आदर्श नहीं है। उनके सामने कोई सामाजिक आदर्श उपस्थित करने में हमारी आज की पीढ़ी नितान्त असफल सिद्ध हुई है। कौनसी सामाजिक पद्धति, कौनसा सामाजिक आदर्श एक आदर्श के रूप में, एक युद्ध घोष के रूप में हमारी पीढ़ी ने उनके सामने दिया है जिसको सुन कर, जिसे देख कर, जिसकी कल्पना करके उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो और वह एक सही रचनात्मक दिशा की ओर बढ़ें? मैं समझता हूं कि आज के शिक्षा-मनीषियों को, शिक्षा-विदों को इस दिशा में सोचना होगा। एक ही युद्ध-घोष हो सकता है समाजवादी समाज की स्थापना का। स्वतन्त्रता के नाम पर देश के लाखों नवजवान आगे बढ़े थे। वह एक राष्ट्रीय लक्ष्य था। अब बदली हालत

में कौनसा सामाजिक आदर्श है जिसकी प्रेरणा लेकर युवक और छात्र आगे बढ़े ? वह समाजवाद की स्थापना का ही हो सकता है। मान्यवर, हालत आज अत्यन्त गम्भीर है। एक जमाना, था, जब छात्रों और युवकों के आदर्श गांधी जी, सरदार भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, जय प्रकाश और जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। युवक उनके बारे में सोचते थे कि वह क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सोचते है, क्या चाहते हैं और उस पर चलने का प्रयास वह करते थे। लेकिन आज युवकों और छात्रों के आदर्श सिनेजगत के अभिनेता और अभिनेत्रियां हो गई हैं। यह जीवन की भयानकता है। इस भयंकर स्थिति से हमें युवक समाज को और छात्र समुदाय को निकालना है।

शिक्षा जगत में जो अशांति और असन्तोष है, अनरेस्ट और टर्मायल है, यह केवल भारत में ही नहीं है। इसकी परिसीमा यूरोप और अमरीका महाद्वीप तक पहुंच चुकी है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि केवल पूंजीवादी जगत में ही नहीं, समाजवादी जगत के देशों में भी इसकी धमक पहुंच चुकी है। पोलैण्ड, चैकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया आदि में यह अत्यन्त गम्भीर समस्या है, व्यापक समस्या है। इस पर उतनी ही गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। यह विश्व-व्यापी व्याधि हो रही है। मैं चाहूंगा शिक्षा मन्त्री से कि एक हाई पावर कमीशन इसके लिए स्थापित किया जाय–पार्लियामेंट के लेक्चरों से ही सब कुछ नहीं होगा -जिस में एमिनेंट एजूकेशनिस्टस हमारे देश के हों, छात्रों के प्रतिनिधि हों, जो मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि हों, सरकार के भी प्रतिनिधि निश्चय रुप से हों और उन पर अच्छी तरह से विचार-विनिमय करके इस शिक्षा जगत में व्याप्त अनरेस्ट और टरमायल को दूर करने का सद्प्रयास किया जाय।

मान्यवर, शिक्षा का माध्यम जाहिर है कि अपनी मातृभाषा ही होनी चाहिए। जिस भूखंड में जो मातृभाषा हो उसी में सर्वोच्च शिक्षा देने तक की व्यवस्था होनी चाहिये। एक लिंक लैंग्वेज के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हम हिन्दी को विकसित कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि आज 21 साल इस आजादी के हो गये लेकिन उस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। मैकाले की दिखाई हुई दिशा, उसकी विशेष दृष्टि से छोड़े हुए जूठे चरण-चिन्ह, उसके बताए हुए रास्ते पर ही देश को आज भी चलाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं शिक्षा मन्त्री से, वह बताएं इस बात को कि 21 साल में कौन सा प्रयास हुआ इस बात के लिये कि ऐसी शिक्षा पद्धति हम अपनावें जो हमारे देश के वातावरण और जलवायु के अनुकूल हो, जो हमारे देश की मनोदशा के अनुकूल हो, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल हो जो राष्ट्रीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुकूल हो और जिस से हमारे देश को लाभ पहुंचाया जा सके, उस पर कौनसा प्रयास हुआ ? क्या एक भी प्रयास हुआ ? मैं शिक्षा मन्त्री और उनकी सरकार पर चार्ज लगाता हूं कि इस दिशा में कोई भी प्रयास आज तक नहीं हुआ। शिक्षा जगत के संचालन में जैसा कि विधेयक में कहा गया है–छात्रों का भाग अवश्य होना चाहिये। उनके बारे में निश्चय हो और उनको कहने का अधिकार भी न हो, उनकी सलाह तक न ली जाय। जब तक उनका सक्रिय सहयोग न होगा, कोई भी शिक्षा पद्धति नहीं चल सकती। मान्यवर, यह असन्तोष अपरिहार्य है।

18. hrs.

छात्र संगठन अनिवार्य हैं, चाहे छोटी संस्था में हों या विश्वविद्यालय की ऊंची शिक्षा के स्तर पर हों उनका होना अनिवार्य है, उसकी सदस्यता भी अनिवार्य होनी चाहिये। क्यों ? एक छात्र की दो स्थितियां हैं एक तो वह छात्र समुदाय का सदस्य है और दूसरे वह बाहर के

[श्री भारखंडे राय]

उस वर्ग का सदस्य है जिसमें उसके मां–बाप पैदा हुए और रहते हैं। जब तक यह वर्ग असन्तुष्ट है, उसका असन्तोष धधक रहा है, छात्र समुदाय उससे एकदम अछूता रहे, यह सम्भव नहीं है। इसलिए आज की विषमता जब तक नहीं मिटेगी, तब तक छात्र समुदाय का असन्तोष पूरी तरह से समाप्त हो—यह असम्भव बात है। इसलिये में चाहूंगा कि उनकी जो ऐसी समस्यायें हैं—जैसे फीस अधिक ली जाती है, उनको होस्टल में रहने की जगह नहीं मिलती है, मारे-मारे फिरते हैं मामूली मामूली कमरे के लिये, जिन क्लासेज में उनकी पढ़ाई होती है, इतनी भीड़ होती है कि बैठने तक की जगह नहीं होती है, बैन्चें नहीं होती हैं, कुर्सियां नहीं होती हैं, आप स्वयं जाकर देखें, अगर आप अचानक जायं तो देखेंगे कि बहुत सी क्लासों में बीसियों लड़के खड़े हुए लेक्चर सुनते हैं–यह स्थिति आज की शिक्षा संस्थाओं में है। बेकारी का भूत, जैसा हमारे भाई ने कहा–हमेशा उनके सामने मुंह–बाये खड़ा है, जो पूरे समुदाय को ग्रसित कर लेगा, उनका कोई निश्चित भविष्य नहीं है, ऐसी हालत में सिवाय अनार किक–टेन्डेन्सीज पैदा होने के और क्या हो सकता है?

रेजीडेन्शल यूनीवर्सिटीज हमारे देश में बहुत कम हैं। कालेजों और स्कूलों में प्रवेश मे धक्कमधक्का रहने की जगह नहीं है। होस्टलों में रह नहीं पाते–इस तरह एक विशृंखलित छात्र समुदाय को शिक्षा देकर आज का समाज नहीं चल सकता। गुरुजनों का आदर्शहीन जीवन भी उनके अन्दर प्राण नहीं फूंक सकता, जिस गुरुजन का, चाहे किसी भी क्लास का हो, पहले दर्जे को पढ़ाने वाला हो या एम. ए. को पढ़ाने वाला हो, यदि उसका स्वयं का जीवन आदर्श नहीं है, तो उसके आदर्शहीन जीवन से आज का छात्र प्रभावित नहीं हो सकता। इस लिए मैं चाहूंगा कि इन चीजों की ओर आज के समाज को, आज की सरकार को सोचना चाहिए।

वाराणसी यूनीवर्सिटी इसकी एक ताजी नजीर है—वहां पर एक ऐसा घृणित वाइस-चांसलर है, जिसको छात्रों का अपार बहुमत बिलकुल नहीं चाहता, उस को लादा हुआ है, लादा गया है, लाद कर रखा गया है।....

श्री बलराज मधोक : किसी वाइस चांसलर के प्रति घृणित शब्द कहना उचित नहीं है। It means a contemptible person. Mr. A. C. Joshi is one of the most respected Vice-Chancellors and to call him like that is really deplorable.

MR. CHAIRMAN : Why should he use unnecessarily such harsh words ?

श्री भारखण्डे राय : मान्यवर, ऐसा वाइस चांसलर है, जिनके छात्रों का अपार समुदाय उनको नहीं चाहता है, उनको लादा गया है, लादा हुआ है, ऐसी स्थिति में वहां शान्ति कैसे पैदा हो सकती है। वहां के एक सबसे प्रिय छात्र नरेन्द्र सिन्हा को, वन-आफ-दी-मोस्ट-बिलवेड-स्टूडेन्ट, आज भी यूनीवर्सिटी एरिये से बाहर निकाला हुआ है, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। यह स्थिति जब तक रहेगी तब तक शान्ति नहीं आ सकती। ऐसी बहुत सी नजीरें दी जा सकती हैं और एक नहीं अनेक छोटी बड़ी शिक्षा संस्थाओं की दी जा सकती हैं। हाण्डी का एक चावल समझाने के लिये मैंने एक नजीर दी है—ऐसी स्थिति में क्या छात्रों में असन्तोष पैदा नहीं होगा, उनकी आग को दबाया जा सकता है, लेकिन राख डालने से आग समाप्त नहीं होती है, अन्दर ही अन्दर बढ़ती जाती है। इस विश्वव्यापी व्याधि के ऊपर आज का समाज मौजूदा सरकार ध्यान दे।

हमारे शिक्षा मन्त्री एक एमिनेन्ट एजूकेशनिस्ट हैं, लर्नेड आदमी हैं, मैं उम्मीद करता

हैं, वह इस पर विशेष ध्यान देंगे । मैं चाहूंगा कि एक हाई-पावर्ड-कमीशन की स्थापना के बारे में जो बात मैंने कही है, उस पर अपना मत जरूर व्यक्त करेंगे ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़ा मार्मिक प्रश्न सारे विश्व के सामने है और वह प्रश्न है विद्यार्थियों के सम्बन्ध में । एक ही बात मुझे शुरू में कहनी है जैसा कि बार बार हम पुराने लोग दोहराते हैं - लाइक फादर, लाइक सन - पिता के अनुकूल ही सन्तान होती है । ठीक उसी प्रकार राष्ट्र निर्माताओं के अनुकूल ही छात्र होते हैं । शिक्षक, जिन्हे राष्ट्र निर्माता भी कहते हैं, के विषय में अभी हमारे आदरणीय श्री शशिभूषण जी ने जो कहा है, उनके पूर्व आदरणीय वक्ताओं ने भी कहा है कि उनकी कैसी दयनीय स्थिति है, यह सारे देश को मालूम है । आप एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से अलग नहीं कर सकते हैं । आप तो कहेंगे कि महात्मा कबीर की तरह आवो और काम करो, लेकिन कबीर बनने के लिए, रेवोल्यूशनरी बनने के लिए, रहस्यवादी बनने के लिए कितना मनीषी होना जरूरी है, उसके लिए क्या काम करना होगा, उसको भी हमें समझना है । इसलिए मैं सबसे पहले मधु लिमये जी से कहूंगा कि भाई साहब, यूनिवर्सिटीज में छात्र यकायक नहीं उतर आते हैं बल्कि स्कूलों से और विद्यालयों से वहां पर आते हैं । उन स्कूलों और विद्यालयों में उन छात्रों को समय के अनुसार बातें करने, प्रार्थना करने और फिजिकल ट्रेनिंग की समयानुवर्तित्ता की आदत डाली जाती हैं और फिर बाद में वही छात्र विश्वविद्यालयों में पहुंचते हैं । इसलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों पर भी आती है और उसके बाद फिर राष्ट्र निर्माताओं पर आती है । मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात को बड़ी गम्भीरता से सोचा है इसीलिए उन्होंने कैबिनेट में रिशफलिंग की और एजूकेशन के साथ साथ यूथ सर्विसेज का प्रोग्राम भी रखा । इसके पीछे बहुत गम्भीर बातें छिपी हुई हैं । इसलिए मैं मधु लिमये जी से कहूंगा कि भाई साहब सच्ची बातें कभी कभी बड़ी अप्रिय लगती हैं । उनके मुख्य मंत्री श्री महामाया बाबू ने कहा कि ये जिगर के टुकड़े हैं, सही बात है, वे हमारे बच्चे हैं, हमारे सभी कुछ हैं लेकिन विशृंखलता में इतनी लग्जरी लिबर्टी के साथ बेलगाम छोड़ देने से क्या होगा ? डिमोक्रेसी में तीनों पहलू एक साथ चलते हैं । राष्ट्र-निर्माता, विद्यार्थी, चाहे वे विश्वविद्यालय के हों या विद्यालयों के हो, और अभिभावकगण । आज गार्जियन जब विद्यार्थियों से कहते हैं कि विश्वविद्यालय में जाओ तो वे बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं । इसके बाद जो राष्ट्र निर्माता हैं या जो प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, व्याख्याता हैं उनकी आज क्या हालत है वह हमारे कन्डप्पन साहब ने बताई । डी० एम० के० ने प्रोफेसर्स और शिक्षकों से कहा कि आप अलग रहें प्रजातन्त्र में जबकि खुद उनको, एक प्रोफेसर को डी० एम० के० का टिकट मिला । लेकिन आप शिक्षक को अलग नहीं कर सकते हैं । शिक्षक अगर योग्य है, लोकप्रिय है तो उसे आप हटा नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि आप का पार्लमेन्ट या असेम्बली में प्रवेश नहीं होगा । इसलिए मैं मधु लिमये जी से कहना चाहूंगा कि अभिभावक और यूथ की बात डा० राव के पास है, आप डा० राव से मिलकर वह बात उनके सामने रखिये और उनको बताइये ।

मगर बनारस की बात जो हमारे अनुभवी श्री झारखंडे राय जी ने बताई और प्रोफेसर मधोक ने भी कही, वह भीतरी बात बड़ी लज्जास्पद, दर्दनाक है । आप एक खास सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर को कहिये या विद्यार्थी को कहिये लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा है कि एफ्लुएन्ट सोसायटी में भी ये बातें होती हैं । एफ्लुएन्ट सोसायटी में ये बातें हो सकती हैं लेकिन डेवलपिंग कन्ट्रीज में आज आप देखें कि भारत का कल्चर क्या है, आर्यावृत का कल्चर क्या है ? वह चीज गुरुकुल में भी मिलेगी । आज भी संस्कृत की जितनी

[श्री यमुना प्रसाद मंडल]

यूनिवर्सिटीज हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं वहां भी तरह की छोटी मोटी बातें, छोटे मोटे डिस्टर्बेंस होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर वहां के गुरुजन, प्रोफेसर्स, वहां के शिक्षकगण व्याख्याता बहुत सादगी के साथ काम करते हैं, विद्यार्थियों पर उन का असर पड़ता है। जब संस्कृत भाषा को काफी माडर्नाइज नहीं किया गया है, इस में रोटियों का सवाल हल नहीं होता, फिर भी आप देखें कि उस यूनीवर्सिटी में क्यों ये सब बातें नहीं घटतीं ? और मौडर्न यूनीवर्सिटियों में ये सब बातें होती है ? उस के जिम्मेवार बहुत से लोग हैं, शायद हम लोग भी हो सकते हैं। और जब यह प्रजातन्त्र में मतदान की बात आती है तो सच्ची बात क्या है यह सभी जानते हैं, मैं उसे नहीं कहना चाहता। इसलिए सब से बड़ी चीज होती है कि विद्यालय में, चाहे वह माध्यमिक विद्यालय हो, हायर सेकेन्ड्री ऐजूकेशन हो, सेकेन्ड्री ऐजूकेशन हो, वहां हमें बहुत अच्छे ढंग से काम करना है। दिल्ली के स्कूलों में मैं देखता हूं काफी विद्यार्थियों की सीमित संख्या है। आप और शहरों के स्कूलों में चले जाइये वहां जो एक निश्चित और कानूनी ढंग से उस की सीमा होनी चाहिये, लिमिटेड नम्बर आफ स्टूडेंट्स आन दी रोल्स, उसे नहीं रखा जाता है। बिहार के कुछ ऐसे कालेज है जिन के पास अपना मकान, जमीन नहीं, लड़के कहां रहते हैं इस का ठिकाना नहीं। क्या होगा ऐसी हालत में विश्वविद्यालय की सीनेट या सिन्डीकेट को, जब वह मन्जूरी दी जाती है, तो केवल 51,000 रु० जमा कर दें और उस से मन्जूरी मिल जाती है। तो क्या वह शिक्षा को आगे ले चल सकते हैं ? आज मधु भाई यह दावा करते हैं कि इस बिल को सारे देश में फैला देने से सब हल हो जायगा। होगा क्या ? इस का विपरीत असर पड़ेगा और खराब असर इस का होगा। जैसे 1967 के समय विद्यार्थियों को क्या क्या बताया गया किस तरह गोलियां खाने को कहा गया, मेरी कांस्टीटुएंसी, समस्तीपुर में गोली इन्हों ने खिलवादी, उस के बाद फिर बिहार विश्वविद्यालय के राम दयाल कालेज में गोली चली और अध्यापक, विद्यार्थी मारे गये। हम ने यह अनुरोध किया कि जो पहले माध्यमिक शिक्षा है, और उस से भी जो उच्चतर है वहां के शिक्षकों को, वहां के राष्ट्र निर्माताओं को, जिन से नींव वहां डाली जाती है, अगर नींव डालने वाले राष्ट्र निर्माताओं को केवल एक शब्द कह कर ठगते रहें तो ठीक नहीं है।

यह एक बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्र निर्माताओं का हमें पूरे रूप से समादर करना चाहिए। और द्वितीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी ने उस ओर काम शुरू किया था। "टीचर्स-डे" मनाया जाता है। और यह साथ साथ तीनों काम हो जायेंगे, और यह यूथ सर्विस से होगा। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से अपील करूंगा कि आप मधु भाई तथा अन्य शिक्षाविद, अभिभावक, विद्यार्थी प्रतिनिधियों से मिल कर कुछ कीजिये यूथ सर्विसेज से कुछ काम कीजिये। बिल का सर्कुलेशन में भेजने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं इस का विरोध करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : सभापति महोदय, मैं श्री मधु लिमये का जो बिल है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारे विश्वविद्यालय एक परिवार होते हैं इसीलिए हमारी भाषा में उनका नाम गुरुकुल होता था और उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है उनका नाम कुलपति या उपकुलपति होता है। इसीलिए हमारे विश्वविद्यालयों में यह कुल की भावना रहनी चाहिए। यह भी ठीक है कि किसी परिवार के लोग किस प्रकार से आपस में बर्ताव करें और परिवार में किस प्रकार से सद्भावना रहे यह केवल कानून और

कानून की धाराओं से उसका नियमन नहीं हो सकता है बिलकुल ठीक उसी तरीके से "विश्व-विद्यालय की भी बात है। विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालयों के कार्यों में या विद्यार्थियों में जो कुछ त्रुटियां या अशान्ति हम देखते है मैं समझता हूँ कि यूनियन बन जाने से केवल उन की सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी यह एक बहुत बड़ी दुराशा मात्र है परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बिल जिस उद्देश्य से यहां प्रस्तुत किया गया है उस बिल का उद्देश्य तो अच्छा है परन्तु साथ ही साथ दुर्भाग्य हमारा यह है कि आज ससार में यूनियन जो है वह संघर्ष का प्रतीक बन गयी है। यूनियन का अर्थ संघ है। संघ का अभिप्राय यह नहीं है कि वह संघर्ष के लिए बनेगा। संघ को संघर्ष का प्रतीक नहीं होना चाहिए। संघ को तो समता का, स्नेह का, संगठन का और सहानुभूति का प्रतीक होना चाहिए। इसलिए जब विद्यार्थियों में यूनियन बनाने की बात आती है जैसा कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के कालिजों व विश्वविद्यालयों में यूनियन है परन्तु उन यूनियनों में जिस तरीके से काम चलता है जिस तरीके से उनका चुनाव होता है, जिस तरह से चुनावों में पैसा खर्च किया जाता है जिस तरीके से यूनियनों के फंड्स के प्रलोभन के आधार पर चुनाव में लोग खड़े होना चाहते है, और यूनियंस पर कब्जा करना चाहते हैं। यह जो बिल हम ला रहे हैं और जिन यूनियनों का हम ने इस बिल में उल्लेख किया है हमारा यत्न यह होना चाहिए कि आज यूनियंस के कार्य में हम जो गलतियां देख रहे हैं, खामियां देख रहे हैं उन खराबियों को सैंट्रल युनिवर-सिटियों में नही आना चाहिए। श्री शशिभूषण ने जो राजनीतिक बातों की चर्चा की अथवा यह कहा कि राजनीतिक दलों का प्रवेश युनिवरसिटियों में नहीं होना चाहिए इससे उन्होंने असहमति प्रकट की। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी सीखता तो बहुत सी बातें हैं क्योंकि विद्यार्थियों का कार्य ही ज्ञान संग्रह करने का है परन्तु वह सारा ज्ञान संग्रह उसी समय में प्रयोग किया जाय यह कभी नहीं होता है। विद्यार्थी ऊंचा से ऊंचा राजनीति शास्त्र पढ़ें परन्तु यह जो राज-नैतिक दलबन्दी है उस में अगर वह फंस जायगा तो विद्यार्थी के जीवन का अपना जो उद्देश्य विद्या संग्रह करना है उस में बाधा पड़ेगी। इस लिए हमें यत्न करके विश्वविद्यालयों को इस राजनीतिक दलबन्दी से बचाना चाहिए।

आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार मजदूरों में राजनैतिक दल अपनी शक्ति बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं। उसी प्रकार विश्वविद्यालयों में भी राजनैतिक दल अपनी शक्ति बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं। राजनैतिक दल व उसके कार्य-कर्त्ता मुझे माफ करेंगे वैसे मैं भी एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता हूँ, आज हिन्दुस्तान में हालत यह है कि देश में किसी का भी यकीन हो सकता है आज देश में पूंजीपति का यकीन हो सकता है, आज देश में आचार्य का उपकुलपति का यकीन हो सकता है, आज देश में मजदूरों का यकीन हो सकता है, आज देश में सरकारी कर्मचारी का यकीन हो सकता है लेकिन मैं बड़े वेदना भरे शब्दों में कहना चाहता हूँ देश में किसी राजनैतिक व्यक्ति का यकीन नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि जो राजनैतिक क्षेत्र की बुराई है यह कम से कम विश्वविद्यालयों में न आने देनी चाहिए इस विधेयक को बनाते समय ऐसा प्राविधान करना चाहिए ताकि उन राजनैतिक बुराइयों से वह बच सकें।

यूनियन का अभिप्राय यह है कि विद्यार्थी में उत्तरदायित्व की भावना आये। और विद्यार्थियों में केवल अधिकार की भावना आये तो वह सही चीज नहीं होगी। जहां यूनियन के द्वारा आप विद्यार्थियों में अधिकार की भावना जगाना चाहते है वहां उन में कर्त्तव्य की भावना भी जगाइये। इसी के साथ साथ मेरा यह भी निवेदन है कि यूनियन इस बात की जिम्मेदारी लें कि विश्वविद्यालयों में अगर कोई तोड़फोड़ होगी, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

उपकुलपति आदि पर हमला होगा तो उसको दूर करने का या उन उपद्रवों का एक तरीके से निवारण करने की जिम्मेदारी भी यूनियन की होगी। यूनियन के विधान में और यूनियन के नियमों में यह बात भी आ जानी चाहिये कि यूनियन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह युनिवरसिटी कैम्पस में विश्वविद्यालय के क्षेत्र में शान्ति रक्खेगी और विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना पैदा करेगी ताकि विश्वविद्यालय के क्षेत्र में या बाहर कहीं भी विद्यार्थी इस तरह का गैरजिम्मेदाराना काम नहीं करेंगे जिसमे कि राष्ट्र की हानि व अहित होता हो।

इसी के साथ साथ हमें यह भी ऐहतियात करनी होगी कि इन यूनियनों के चुनाव में किसी तरीके से पैसे का इस्तेमाल न हो। आज हम देखते हैं कि जिस प्रकार राजनीतिक चुनावों में पैसे का प्रभुत्व है वही परिस्थिति व्यवहारिक रूप में यूनियनों के चुनावों में भी हो गई है। गरीब आदमी चुनाव में खड़े होने का नाम लेने का साहस भी नहीं कर सकता। यूनियनों के चुनाव में भी 10-20 हजार रुपये खर्च होते हैं, उसी तरह से शराबें चलती हैं और सारे हथकण्डे चलते हैं। बजाय इसके कि हम यूनियनें बना कर उनमें बुराइयां पैदा करें, इस बिल में हमें ऐसे प्रावधान रखने होंगे जिन से यूनियन इन बुराइयों में न फंसे।

आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में ऐसे लड़के भी होते हैं,जिनका उद्देश्य पढ़ना नहीं होता है, जिन्हें बाहर से राजनीतिक के लोग या निहित स्वार्थी इस लिए पैसा देते हैं कि वह विश्वविद्यालयों में जिन लोगों ने उन्हें भेजा है, जिनके पे रोल पर वे हैं, उनका काम करते रहें और विद्यार्थियों को गुमराह करते रहें। इस प्रकार के तत्वों से भी यूनियनों को बचाना होगा। इस लिये जब हम यूनियनों के लिये नियम बनायें तो कमसे कम उनमें यह बात जरूर रक्खे कि जो विद्यार्थी एक दफा या दो दफे फेल हो चुका है वह कभी भी यूनियन का अधिकारी नहीं बन पायेगा। आज ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो पांच छः दफे फेल हो चुका हैं। वह वहां पर इस लिए रहते हैं कि बाहर से उनको पैसा मिलता हैं। बाहर जा कर भी नौकरी करनी है, जब उनको वह पैसा युनिवर्सिटी में ही मिल जाता है तब वह वहां ही रहते है और विश्वविद्यालयों का वातावरण खराब करते है। इसलिए हम जब भी यूनियनों की बात करें तब हम यह एहतियात रक्खें कि जो विद्यार्थी फेल हो चुका है और जिसका पेशा बन गया है कि वह बहिर्मुख बना रहे, वह वहां न रहने पाये। उनको अन्तर्मुख होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि :

सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्।
सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम् विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्।

विद्यार्थी और सुखार्थी बिल्कुल अलग चीजें है। जो विद्यार्थी सुखार्थी हो उसे विद्या नहीं मिल सकती और जो विद्यार्थी विद्या चाहेगा उसे सुख का ध्यान छोड़ना होगा। इसलिए जो विद्यार्थी आश्रम का क्षेत्र है वह बड़ी साधना और तपस्या का क्षेत्र है, उसमें सुख की कहीं गुजाइश नहीं है। इस लिए यूनियन बनाते समय हमें साफ कर देना चाहिए कि जो इस प्रकार के तत्व विश्वविद्यालयों में हैं जो विश्वविद्यालयों के वातावरण को खराब कर रहे हैं, उन से हम बचें, यूनियनें जो हैं वह रचनात्मक काम की प्रवृत्ति लोगों में पैदा करे, वे संघर्ष की प्रतीक न बन कर निर्माण के काम के अपने को प्रवृत्त कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, विद्यार्थी हमारे समाज की जड़ हैं

और वह हमारे भावी नेता हैं, **दे आर दि फीम आफ दि सोसायटी** : यूनिवर्सिटियों में जो यूनियनें कायम की जा रही हैं, वह कोई गलत चीज नहीं है । हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं हम लोग अपनी यूनियन बनाते थे । विद्यार्थियों की यूनियनें इस लिए होती हैं कि वह अपना संगठन ठीक से करें । आखिर कालेज और यूनिवर्सिटी क्या है । वह ट्रेनिंग ग्राउन्ड हैं जहां विद्यार्थियों की ट्रेनिंग होती है, जहां उन्हें अच्छे नागरिक बनाया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस दिल्ली में ही विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने के लिए कालेजों में माक पार्लियामेंट होती है । लड़के पढ़ने के समय में ही हमारी नकल कर के अच्छे सिटिजेन बन कर आ रहे हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम उनको अच्छी ट्रेनिंग दे । गार्जियन की हैसियत से, उनके उस्ताद की हैसियत से और मां बाप की हैसियत से यह हमारी ड्यूटी है । अभी मेरे मित्र श्री शास्त्री ने एक श्लोक सुनाया :

सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्।
सुखार्थी वा त्यजेत् विद्याम् विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्।

यह सत्य है क्योंकि हमारे ऋषियों ने बतलाया कि हमारे जीवन के चार अंग हैं, ब्रह्मचर्य हैं, गृहस्थ आश्रम, वाणप्रस्थ आश्रम और तब जाकर सन्यास आश्रम । ब्रह्मचर्य आश्रम में सारा ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था होती है । उस समय हम विद्यार्थियों को सुयोग्य बना कर ले आये क्योंकि वही हमारे नेता आगे चल कर होंगे । मैं चाहता हूं कि वह अच्छे समाज के, उत्तम समाज के अंग बन कर विद्यालयों से आये ।

श्री झारखण्डे राय ने कहा कि इस देश में शिक्षा का कोई सिद्धान्त नहीं है । मैं उनसे सहमत हूँ क्योंकि पिछले बीस वर्षों में हमने सिर्फ मेकाले की नकल की है । हम अंग्रेजी के पीछे दीवाने हैं । मद्रास से ले कर उत्तर भारत तक यही झगड़ा है । यहां पर लैंग्वेज प्राब्लेम है और यह झगड़ा उसी पर बेस्ड है ।

बाहर का पैसा हमारे देश में खर्च होता है, बाहरी एलीमेंट्स हमारे देश में काम कर रहे है । वे हमारे देश को संगठन बनने नहीं देते हैं । मैं चाहता हूं कि लिमये साहब भारतीय संस्कृति पर अपने आपको आधारित करें । मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के वह बहुत प्रेमी हैं । वे चाहते है कि इनमें ही बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो । बच्चा पहले दिन से ही अपने मां बाप से शिक्षा ग्रहण करने लग जाता है, शिक्षित होने लग जाता है । वही भाषा वह पहले पहल सीखता है । अगर उसकी भाषा में उसको शिक्षा दी जाए तो उसका आधा समय बच सकता है । अंग्रेजी चूंकि हमने अपने विद्यार्थियों पर लाद रखी है, इस वास्ते हमारे देश का नुक्सान हो रहा है । आप से पहले जो शिक्षा मन्त्री थे उन्होंने थ्री लैंगुएज फार्मुला रखा था । वह बहुत सुन्दर फार्मुला था । उस पर अमल होना चाहिए ।

सभापति महोदय आपने देखा होगा कि उर्दू पर यहां बड़ी बहस हुई थी । वह हमारे प्रान्त की भाषा है । मै भी कल उस पर बोलना चाहता था लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला । हमारे लोग उर्दू भी पढ़ते हैं और हिन्दी भी पढ़ते हैं । दोनों भाषायें पढ़ते हैं । उसका आदर होना चाहिए । हम चाहते हैं कि हमारी मातृ भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए और इस तरह से उनका आधा समय बचाया जाए ।

मैं यह भी चाहता हूं कि यूनिवर्स्टीज में मैथेमेटिक्स कम्पलसरी कर दिया जाए । अगर ऐसा किया गया तो अनुशासनहीनता का जो झगड़ा हैं वह कल हल हो जाएगा । जब बसु का अलजबरा पढ़ाया जाता था तब हमारे लड़के सिनेमा नहीं जाते थे । आज सिनेमा संसार ने हमारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी है । जिस नौजवान को देखो वह सिनेमा के गाने गा रहा है, एक्ट्रेसिस की फोटो लिए हुए घूमता है । हमारी सोसाइटी किधर जा रही हैं, नौजवान किधर जा रहे हैं ? ऐसी

[श्री शिव नारायण]

ही हालत रही तो विद्यार्थी वर्ग हमको रिप्लेस नहीं कर सकेगा ।

संयोग से मैं भी एक छोटा मोटा अध्यापक रहा हूं । मैं प्राईमरी का, हायर सैकेन्डरी का, हाई स्कूल का अध्यापक रहा हूं । मैं कह सकता हूं कि अगर बाप और बेटे का सम्बन्ध अच्छा रहेगा, बेटा बाप की बात को मानता रहेगा तो कोई भी उस्ताद बच्चों को अपनी हकूमत पर रख सकता है । लेकिन इसके साथ-साथ हमारे प्रोफेसर साहब मुझे माफ करें अगर मैं यह कहूं कि आज बड़े बड़े प्रोफेसर लोग जो हैं वे केवल किताबे लिखने में लगे रहते हैं, उसी के पीछे दीवाने रहते हैं और लड़कों की तरफ उतना ध्यान नहीं देते जितना देना चाहिये । घर में बैठ कर भी वे किताबें लिखते रहते हैं । यूनियन से ही यूनिटी होगी और उससे हमारे देश का डिवेलेपमेंट होगा । यह ठीक बात है ।

देश को हमें बिगाड़ना नहीं है, बनाना है । यह हमारी जिम्मेदारी है । मैं शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अध्यापकों की तरफ भी ध्यान दें । सुदामा और कृष्ण का आदर्श लाने की आज आवश्यकता हैं । कृष्ण बहुत बड़े थे लेकिन सुदामा छोटे थे । लेकिन जब दोनो मिले तो भ्रातृत्व की भावना से । उनका आपस में प्रेम रहा । लेकिन आज वह बात नहीं है । आज इस आदर्श की स्थापना हमको देश में करनी है ।

हमारे बच्चों को जो वजीफा मिलना होता है उसको ये लोग खा जाते है । मैनेजमेंट में बडी गन्दगी है। मैंने चागला साहब से प्रार्थना की थी कि हिन्दुस्तान की शिक्षा को आप नैशनलाइज करो । मौनोपोलिज़ को आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शिक्षा को तो आप नैशनलाइज करो इसको तो आप अपने कन्ट्रोल में रखो । अगर आपने ऐसा किया तभी अच्छे नागरिक बन सकेंगे । आज शिक्षा जगत में बड़ी कमियां है । फिर मौका जब मिलेगा तब मैं उन कमियों की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाऊंगा । हमारे वर्तमान शिक्षा मन्त्री गुरु रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, डाक्टर हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं । उनको जब यह पद मिला तो उसका देश ने स्वागत किया । हमने उनको वैलकम किया

MR. CHAIRMAN : The hon. Member will continue his speech on the next non-official day.

We will now take up the Half- an-hour discussion.

18.29 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION
Students Unrest in India

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, आज देश के सामने जो एक अति गम्भीर समस्या है उसकी तरफ मैं मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । चूंकि मन्त्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक इस समस्या पर विचार करते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस वाद-विवाद के द्वारा जो भी रचनात्मक सुझाव उनके सामने उपस्थित किये जायेंगे उन पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उन को अमल में लाने का प्रयत्न करेंगे ।

आज विद्यार्थियों में अशान्ति है, क्षोभ है, असन्तोष है और वह क्षोभ इस प्रकार का रूप धारण करता जा रहा है जिससे सभी देश वासियों को चिंतित होना स्वाभाविक है । अनेकों स्थानों पर इसका भीषण स्वरुप प्रकट हुआ है, अनेको स्थानों पर इसने हिंसात्मक रूप धारण किया है, अनेकों स्थानों पर विश्वविद्यालयों की सम्पति जलाई गई है । अन्य सरकारी सम्पत्ति जलाई गई है, रेलवे विभाग की सम्पत्ति जलाई गई है या उसको नष्ट भ्रष्ट किया गया है । मैं